माघ शुक्ल - 11 ■ संवत 2081 ■ वर्ष - 20 ■ अंक - 194 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- बेंगलूरु » शनिवार » 08-02-2025 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 मणिपुर की एन. बीरेन सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस

6 पंजाब में फैलता ईसाई मिशनरियों का जाल !

7 'गुम है किसी के प्यार में' गाना मेरे दिल के बहुत करीब : रेखा

फर्स्ट टेक

विशाखापत्तनम में दक्षिण तटीय रेलवे जोन के गठन को मंजूरी

नई दिल्ली/एजेन्सी। मंत्रिमंडल ने विशाखापत्तनम में प्रस्तावित दक्षिण तटीय रेलवे जोन के गठन के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि यह निर्णय आंध्र प्रदेश पुनर्गठन से संबंधित वायदे के अंतर्गत किया गया है। उन्होंने बताया कि इस नए रेल जोन के गठन के बाद भी खंडित वाल्टेयर डिवीजन बरकरार रहेगा। मंत्रिमंडल ने इस डिवीजन के क्षेत्राधिकार में संशोधन के प्रस्ताव को को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि आंध्र पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार नया रेलवे ज़ोन 'साउथ कोस्ट रेलवे ज़ोन' बनाया गया है। फैसले के अनुसार पूर्व तटीय रेलवे जोन में नया डिवीजन रायगडा रेलवे डिवीजन होगा। अब वाल्टेयर डिवीजन का नाम विशाखापत्तनम रेलवे डिवीजन रखा गया है।

नीट-यूजी परीक्षा चार मई को आयोजित की जाएगी

नई दिल्ली/भाषा। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी चार मई को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हुई और सात मार्च को समाप्त होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या के लिहाज से यह देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है। वर्ष 2024 में रिकॉर्ड 24 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। एनटीए हर साल मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट का आयोजन करता है। एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए कुल 1,08,000 सीटें उपलब्ध हैं। इनमें से लगभग 56,000 सीटें सरकारी अस्पतालों में और लगभग 52,000 सीटें निजी कॉलेजों में हैं।

यौन उत्पीड़न में शामिल शिक्षकों की डिग्री रद्द की जाएगी : तमिलनाडु के मंत्री

चेन्नई/भाषा। तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी ने शुक्रवार को कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोपी शिक्षकों के डिग्री प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। कृष्णागिरि जिले के एक सरकारी मध्य विद्यालय में तीन शिक्षकों द्वारा 13 वर्षीय छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न की घटना के बारे में मीडियाकर्मियों के एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, ''अब से हम केवल कानूनी कार्रवाई तक ही सीमित नहीं रहेंगे। यौन उत्पीड़न में शामिल शिक्षकों के प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे।''

08-02-2025 सूर्यास्त 6:23 बजे | 09-02-2025 सूर्योदय 6:44 बजे

BSE	NSE
77,860.19	23,559.95
(-197.97)	(-43.40)

सोना	चांदी
8,907 रु.	98,593 रु.
(24 कैरेट) प्रति ग्राम	प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

विचार करें

जो परदेश गया हर कोई,
सतवादी ना गाँधी है।
पैसे वालों ने ही समझो,
ये तरकीबें साधी है।।
मर्यादाओं को तोड़े तो,
समझो कीमत आधी है।
गया अवैध तरीकों से वो,
सच में तो अपराधी है।।

आरबीआई ने पांच साल बाद रेपो दर 0.25 प्रतिशत घटाई

मकान, वाहन समेत विभिन्न ईएमआई में कमी आने की उम्मीद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

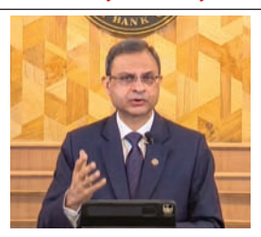

मुंबई/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को सुस्त पड़ रही अर्थव्यवस्था को गति देने के मकसद से लगभग पांच साल बाद प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.25 प्रतिशत घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया।

रेपो दर घटने का मतलब है कि मकान, वाहन समेत विभिन्न कर्जों पर मासिक किस्त (ईएमआई) में कमी आने की उम्मीद है।

आरबीआई के नवनियुक्त गवर्नर संजय मल्होत्रा ने छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बुधवार से शुरू तीन दिन की बैठक में लिए गये निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि समिति ने आम सहमति से रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती का निर्णय किया है।

इसके साथ, एमपीसी में अपने रुख को 'तटस्थ' बनाये रखने पर सहमति बनी है।

रेपो दर वह प्रमुख ब्याज है, जिसपर वाणिज्यिक बैंक अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिये केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। आरबीआई मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिये इस दर का उपयोग करता है। रेपो दर अधिक होने का मतलब है कि कर्ज की लागत अधिक होगी। यानी ग्राहकों को अधिक ब्याज पर कर्ज मिलेगा। वहीं इसके उलट, रेपो दर कम होने से आवास, कार और व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज दर घटने की उम्मीद रहती है।

साथ ही रेपो दर बचत और निवेश उत्पादों पर रिटर्न भी तय करती है। उच्च रेपो दर से सावधि जमा और अन्य बचत उत्पादों पर बेहतर रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि बैंक जमा को आकर्षित करने के लिए उच्च ब्याज दर की पेशकश करते हैं। दूसरी ओर, कम रेपो दर इन बचत उत्पादों पर अर्जित ब्याज को कम कर सकती हैं।

इससे पहले मई, 2020 में कोविड-19 महामारी के समय रेपो दर को 0.40 प्रतिशत घटाकर चार प्रतिशत किया गया था। फिर रूस-यूक्रेन युद्ध के जोखिमों से निपटने के लिए आरबीआई ने मई, 2022 में दरों में बढ़ोतरी करनी शुरू की थी और यह सिलसिला फरवरी, 2023 में जाकर रुका था। रेपो दर करीब दो साल से 6.50 प्रतिशत पर स्थिर थी।

भारत संवैधानिक रूप से दुनिया का एकमात्र देश जिसमें हर स्तर पर लोकतांत्रिक प्रणाली है

न्यायपालिका तक पहुंच को 'हथियार' बनाया जा रहा है : धनखड़

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/भाषा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि न्यायपालिका तक पहुंच को इस तरह से 'हथियार' बनाया गया है, जो दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं हो रहा है।

देश के भीतर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयासों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, ''सबसे पुराने लोकतंत्र, सबसे मजबूत लोकतंत्र, सबसे प्रगतिशील लोकतंत्र और सबसे जीवंत लोकतंत्र वाले देश में – और संवैधानिक रूप से दुनिया का एकमात्र देश जिसमें हर स्तर पर लोकतांत्रिक प्रणाली है, चाहे वह गांव हो, शहर हो, राज्य हो या राष्ट्र हो – हमारी चुनावी प्रक्रिया को इस तरह से प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए।''

वह हावेरी जिले के राणेबेन्नूर में आयोजित कर्नाटक वैभव साहित्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव के तीसरे संस्करण के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। धनखड़ ने कहा कि विभाजनकारी ताकतें अलग-अलग तरीकों से काम करती हैं। धनखड़ ने कहा, ''इन ताकतों ने नये-नये रास्ते अपनाए हैं और बहुत से मुद्दों पर आप देखेंगे कि वे न्यायपालिका की शरण में जाते हैं।''

उन्होंने दावा करते हुए कहा, ''मैं चिंतित हूं, क्योंकि हमारे देश के संविधान ने न्यायिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को अधिकार दिया है। और वह अधिकार क्या है? न्यायालय की शरण लेने का अधिकार। हालांकि, हाल के वर्षों में, राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए धन का इस्तेमाल किया गया है, और न्यायपालिका तक पहुंच को हथियार बनाया गया है, और यह इस तरीके से हो रहा है, जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं हो रहा है।''

उन्होंने कहा, ''राष्ट्र को चुनौती देने वाली, जो राष्ट्रवाद एवं क्षेत्रवाद के बीच टकराव पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें बहुत करारा जवाब मिलना चाहिए। वे हमारी सांस्कृतिक विरासत को कमजोर करना चाहते हैं।'' राष्ट्र के सांस्कृतिक दर्शन को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए धनखड़ ने कहा, ''आज के दिन, जब मैं एक तरफ देखता हूं, तो भारत की प्रगति को दुनिया की नजर से देखना चाहिये, राष्ट्र के अंदर बसने वाले लोगों की नजर से देखो, तो वो बारिश में नाचते हुए मोर के पंख की तरह हैं...लेकिन जब मैं मोर के पैरों को देखता हूं, तो मुझे चिंता होती है, सोचने पर मजबूर हो जाता हूं और फिर मुझे अपने सांस्कृतिक दर्शन की आवश्यकता महसूस होती है। हम उसी शाखा को काटने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर हम पनप रहे हैं, जिस पर हम बैठते हैं।''

दिल्ली की सत्ता पर कौन होगा काबिज

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना आज

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

■ कई एग्जिट पोल ने भाजपा को आप पर बढ़त दिखाई है, जो 2015 से दिल्ली में सत्ता में है।

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती शनिवार को होगी, जिससे यह तय होगा कि आम आदमी पार्टी (आप) चौथी बार सत्ता में आएगी या फिर 27 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा सरकार बनाएगी।

पिछले दो विधानसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीतने के बाद कांग्रेस भी इस बार कुछ बढ़त की उम्मीद कर रही है। कई एग्जिट पोल ने भाजपा को आप पर बढ़त दिखाई है, जो 2015 से दिल्ली में सत्ता में है।

मतगणना की प्रक्रिया सुबह आठ बजे शुरू होगी और शुरुआती रुझान शुरुआती घंटों से ही आने शुरू हो जाएंगे। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, दिल्ली चुनाव के लिए बुधवार को 60.54 फीसदी वोट पड़े।

भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है कि उनकी पार्टी करीब 50 सीटें जीतेगी। वहीं, आप ने एग्जिट पोल के अनुमानों को खारिज करते हुए कहा कि वह फिर से सरकार बनाएगी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) एलिस वाज ने कहा कि मतगणना पर्यवेक्षकों, मतगणना सहायकों और प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित सहायक कर्मचारियों सहित कुल 5,000 कर्मियों को शनिवार को मतगणना के लिए तैनात किया जाएगा। मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच वीवीपैट (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स) का यादृच्छिक चयन किया जाएगा।

इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना के मद्देनजर 19 मतगणना केंद्रों के लिए अर्धसैनिक बलों की दो कंपनियों और दिल्ली पुलिसकर्मियों सहित तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

मतगणना के दिन सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, ''हमने (मतगणना के दिन) सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मतगणना केंद्रों के अंदर केवल अधिकृत कर्मियों को ही जाने की अनुमति होगी, जहां मोबाइल फोन का उपयोग सख्त वर्जित होगा।''

विदेशी जेलों में बंद हैं 10,152 भारतीय : सरकार

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि वर्तमान में विदेशी जेलों में बंद भारतीय कैदियों की संख्या 10,152 है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इस संबंध में देश-वार डेटा साझा किया। उनके द्वारा साझा किए गए आंकड़ों में सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, श्रीलंका, स्पेन, रूस, इज़राइल, चीन, बांग्लादेश और अर्जेंटीना सहित 86 देशों में जेलों में बंद भारतीय कैदियों के आंकड़े शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि 2,633 भारतीय कैदी सऊदी अरब की जेलों में बंद हैं और 2,518 ऐसे कैदी संयुक्त अरब अमीरात की जेलों में हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक, नेपाल की जेलों में 1,317 भारतीय कैदी हैं, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका में यह संख्या क्रमशः 266 और 98 है। सिंह ने कहा, ''मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्तमान में विदेशी जेलों में विचाराधीन कैदियों सहित भारतीय कैदियों की संख्या 10,152 है।''

अदाणी के छोटे बेटे की शादी संपन्न, दस हजार करोड़ रुपए दान करने की घोषणा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अहमदाबाद/भाषा। अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी के छोटे बेटे जीत शुक्रवार को अपनी मंगेतर दिवा शाह के साथ एक निजी पारंपरिक समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। शादी के समारोह में उनके दोस्तों और परिवार के लोगों का एक छोटा समूह ही मौजूद था।

गौतम अदाणी ने इस वैवाहिक समारोह को साधारण ढंग से संपन्न कराने को प्राथमिकता दी। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कौशल विकास में बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए 10,000 करोड़ रुपये दान करने की घोषणा की।

सूत्रों ने कहा कि यहां शांतिग्राम में जैन परंपरा के अनुरूप की गई शादी के लिए बहुत कम संख्या में परिवार और दोस्तों को आमंत्रित किया गया था। सूत्रों के मुताबिक, शादी में किसी भी मशहूर हस्ती को आमंत्रित नहीं किया गया था। अदाणी शनिवार को कर्मचारियों के लिए एक भोज का आयोजन करेंगे।

2,000 करोड़ के फेमा मामले में इरोस इंटरनेशनल पर ईडी का छापा

नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने 2,000 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन मामले की जांच के तहत हाल में प्रमुख मनोरंजन कंपनी इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड और इससे संबद्ध कुछ कंपनियों के खिलाफ छापेमारी की। जांच एजेंसी ने बताया कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत पांच फरवरी को मुंबई में पांच स्थानों पर छापेमारी की गई। प्रतिक्रिया के लिए कंपनी से संपर्क नहीं हो पाया। ईडी ने एक बयान में कहा कि ये तलाशी इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड और इरोस समूह की अन्य कंपनियों द्वारा कोष के हेरफेर के मामले में जारी जांच का हिस्सा है। विदेशी कंपनियों, अचल संपत्तियों, विदेशी बैंक खातों और डिजिटल उपकरणों से संबंधित कई दस्तावेज जब्त किए गए। ईडी ने कहा कि जांच इरोस समूह और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की जांच के आधार पर शुरू की गई थी।

महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ श्रद्धालु लगा चुके डुबकी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

■ अभी महाकुंभ मेला संपन्न होने में 19 दिन शेष हैं और ऐसे में सरकार का अनुमान है कि डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ के पार जा सकता है।

महाकुंभ नगर/भाषा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से आयोजित महाकुंभ में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में अब तक डुबकी लगाने वाले साधु-संतों और श्रद्धालुओं, कल्पवासियों की संख्या 40 करोड़ के पार पहुंच गई है। सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक, शुक्रवार सुबह तक महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं और अकेले शुक्रवार को सुबह 10 बजे तक 42.07 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया।

अभी महाकुंभ मेला संपन्न होने में 19 दिन शेष हैं और ऐसे में सरकार का अनुमान है कि डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ के पार जा सकता है। तीनों अमृत स्नान (मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी) के बाद भी श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। देश और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं।

इस भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने 12 फरवरी तक माध्यमिक स्कूलों की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया है ताकि छात्र-छात्राओं को असुविधा न हो। बयान के मुताबिक, ''सर्वाधिक आठ करोड़ श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या पर स्नान किया था, जबकि 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर डुबकी लगाई।

महाकुंभ मेले में इस्कॉन के शिविर में आग लगी, कोई हताहत नहीं

महाकुंभ नगर/भाषा। महाकुंभ नगर के सेक्टर-18 में स्थित अंतरराष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ (इस्कॉन) के शिविर में शुक्रवार सुबह आग लग गई जिसमें करीब 20 से 22 टेंट जलकर खाक हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि दमकलकर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया है और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, ''सेक्टर-18 स्थित इस्कॉन के शिविर में सुबह 10 बजकर 35 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली। तत्काल कदम उठाते हुए दमकल केंद्र से 12 गाड़ियां रवाना की गईं और करीब आधा घंटे में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।'' उन्होंने बताया कि 20 से 22 टेंट जलकर खाक हो गए हैं और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि हवा तेज होने के कारण पास के अतुलेश्वर धाम और देवी संपत्ति के कुछ शिविर भी आग की चपेट में आ गए। शर्मा ने बताया कि इस्कॉन के शिविर में हर टेंट में एसी, ब्लोअर और हीटर लगे थे, संभवतः शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी।

विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप

एसीबी ने केजरीवाल को जांच के सिलसिले में नोटिस दिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल को कानूनी नोटिस देकर उनके उन आरोपों के बारे में विवरण और सबूत मांगे हैं, जिनमें उन्होंने कहा था कि भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों से पहले उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की खरीद-फरोख्त का प्रयास किया। शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाने से एक दिन पहले यह नोटिस दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को उस समय राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई, जब एसीबी की एक टीम अरविंद केजरीवाल के 5, फिरोजशाह रोड स्थित आवास पर पहुंची।

इससे एक दिन पहले ही केजरीवाल ने भाजपा पर आठ फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से पूर्व पार्टी के 16 उम्मीदवारों को खरीदने का प्रयास करने का आरोप लगाया था।

मंत्रिमंडल ने नए आयकर विधेयक को मंजूरी दी, अगले हफ्ते संसद में होगा पेश

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को नये आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी, जो छह दशक पुराने आईटी अधिनियम की जगह लेगा। सूत्रों ने यह जानकारी दी। नया विधेयक प्रत्यक्ष कर कानून को समझने में आसान बनाने और कोई नया कर बोझ नहीं लगाने की एक कवायद है। इसमें प्रावधान और स्पष्टीकरण या कठिन वाक्य नहीं होंगे। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने नये आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि नया आयकर विधेयक अब अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा और इसे संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा।

सम्मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

करुनाडु डॉ राजकुमार अभिमानी गळा संघ महालक्ष्मीपुरम द्वारा आयोजित अणम्मा देवी उत्सव कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि महेंद्र मुणोत ने देवी मां के दर्शन कर आशीर्वाद लिया एवं अन्नदान कार्यक्रम में सेवा प्रदान की। आयोजकों ने मुणोत को सम्मानित किया।

आरबीआई ने एलसीआर नियमों को एक साल के लिए टाला, नियामकीय सख्ती में नरमी के संकेत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को बैंकों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि नकदी कवरेज अनुपात (एलसीआर) के कार्यान्वयन को कम-से-कम एक साल के लिए टाल दिया जाएगा। उन्होंने इस चरणबद्ध तरीके से लागू करने का भरोसा भी दिलाया।

दिसंबर में आरबीआई गवर्नर बनने के बाद मल्होत्रा ने मीडिया के साथ अपनी पहली बातचीत में कहा कि वित्तीय स्थिरता महत्वपूर्ण है, लेकिन केंद्रीय बैंक संसाधनों का कुशल उपयोग करने के लिए विनियमन की लागत पर भी विचार करेगा। पिछले गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्तीय स्थिरता पर ध्यान देने के साथ विनियामक कार्रवाई के मामले में अधिक सख्त रुख अपनाया था।

बैंकों और कुछ विश्लेषकों का कहना था कि कि कई कदमों ने अर्थव्यवस्था में ऋण वृद्धि रोक दी है। मल्होत्रा ने एक बयान में कहा, ''हम मानते हैं कि जिस तरह कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, उसी तरह स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाने के लिए विनियमन भी लागत से रहित नहीं है... हम प्रत्येक विनियमन के लाभ और लागत को ध्यान में रखते हुए, सही संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे।'' एलसीआर के संदर्भ में गवर्नर ने कहा कि बैंकों के पास इस साल 31 मार्च तक इसे लागू करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है।

ऐसी स्थिति में इसे कम-से-कम 31 मार्च 2026 से पहले लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंकों को कम से कम इतना समय देने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने यह भरोसा भी दिया कि एलसीआर ढांचे को चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाएगा। इसी तरह, एचडीएफसी बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक जैसी प्रमुख संस्थाओं के खिलाफ उठाए गए कदमों पर नए गवर्नर ने कहा कि उनका मानना है कि ये अंतिम उपाय हैं।

उन्होंने कहा कि जब बाकी सभी उपाय विफल हो गए हों, तभी इनका इस्तेमाल करना चाहिए।

एटीएम में पैसा भरने के बहाने पैसा चुराने वाले 6 लोग गिरफ्तार

बेंगलूरु। महालक्ष्मीलेआउट पुलिस थाना के अधिकारियोंने कैम्पेगौड़ा लेआउट से एटीएम में पैसा डालने वाले एजेंसी के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पत्रकार वार्ता में नगर पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने बताया कि पुलिस ने एटीएम वैन लोडिंग कैश अधिकारी समीर (26), कैश लोडर मनोहर(29) व गिरीश (26), जग्गेश (28) व ड्राइवर शिबू (27) व यशवंत (27) को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया कि ये आरोपी एटीएम में पैसा डालने का कार्य करते थे और मिलकर आधा पैसा एटीएम में डालते थे और आधा पैसा चुरा लेते थे। महालक्ष्मी लेआउट व नन्दिनी लेआउट के आसपास के क्षेत्र से एटीएम में पैसा जमा करने में अनियमिताओं की शिकायत आ रही थी जिसके चलते पुलिस ने निगरानी कर इन लोगों को पकड़ा है जिनके पास से 52 लाख रुपए नगद और 90लाख रुपए मूल्य की तीन कारें बरामद की गई है।

बेंगलूरु इलेक्ट्रानिक्स एसोसिएशन ने एसपी रोड निर्माण कार्य का किया निरीक्षण

बेंगलूरु। बेंगलूरु इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने शुक्रवार को एसपी रोड, नगरथपेट, ओटीसी रोड पर बीबीएमपी द्वारा किए जा रहे पाइपलाइन के कार्यों का निरीक्षण किया। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ललित डाकलिया सहित एसोसिएशन के सदस्यों ने बीबीएमपी इंजीनियर्स और ठेकेदार से बातचीत कर एसपी रोड, ओटीसी रोड में ग्राहकों और दुकानदारों के सुगम प्रवेश के लिए रास्ता खोलने के बारे में जानकारी प्राप्त की और जारी कार्यों का निरीक्षण किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल वरन्दानी ने बताया कि अधिकारियों ने बताया कि वाईट टॉपिंग का कार्य तेज करने की बात कही। एसोसिएशन के महामंत्री अरुण लुणावत ने बताया कि इस बारे में ट्रैफिक पुलिस, बीबीएमपी, एफकेसीसीआई आदि को पत्र लिखकर कार्य को तेज करने की अपील की।

देश निश्चित रूप से सात प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर हासिल कर सकता है : आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा कि भारत निश्चित रूप से सात प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है और देश को इसे हासिल करने की आकांक्षा करनी चाहिए।

रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। यह चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित 6.4 प्रतिशत से अधिक है।

यह पूछे जाने पर कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के तेज गति से बढ़ने की संभावना है, उन्होंने कहा, ''...निश्चित रूप से भारत सात प्रतिशत और उससे अधिक की वृद्धि दर हासिल कर सकता है। हमें निश्चित रूप से इसकी आकांक्षा करनी चाहिए।''

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि आयकर राहत से मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी, बल्कि आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलेगा।

सीतारमण ने नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय को पूरी तरह से कर से छूट देने की घोषणा की है। साथ ही कर स्लैब में भी बदलाव किया है।

नई कर व्यवस्था में कर छूट सात लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए किये जाने से एक करोड़ करदाताओं को लाभ होगा।

मल्होत्रा ने चालू वित्त वर्ष की आखिरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति दोनों नजरिये से 'उत्कृष्ट' है।

बजट में कृषि पर ध्यान केंद्रित करने से दलहन, तिलहन और अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी और खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आएगी।

आरबीआई ने अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 4.2 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया है, जबकि 2024-25 के लिए पहले के 4.8 प्रतिशत के अनुमान को बरकरार रखा है।

पंजीकृत गैर-बैंकिंग ब्रोकर को एनडीएस-ओएम तक मिलेगी सीधी पहुंच: आरबीआई

मुंबई/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि बाजार नियामक सेबी के साथ पंजीकृत गैर-बैंकिंग ब्रोकर अपने ग्राहकों की तरफ से सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मंच एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुंच हासिल कर सकते हैं। फिलहाल 'नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम- ऑर्डर मैचिंग' (एनडीएस-ओएम) मंच तक पहुंच विनियमित इकाइयों ओर बैंकों एवं प्राथमिक डीलरों के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।

आरबीआई ने कहा, ''इस पहुंच का दायरा बढ़ाने के इरादे से यह निर्णय लिया गया है कि सेबी के साथ पंजीकृत गैर-बैंकिंग ब्रोकर अपने ग्राहकों की ओर से सीधे एनडीएस-ओएम तक पहुंच बना सकते हैं।'' सेबी के साथ पंजीकृत ब्रोकर इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन एनडीएस-ओएम तक पहुंच बना सकते हैं। इस बीच, आरबीआई ने 'विनियमित बाजारों के कारोबार एवं निपटान समय की व्यापक समीक्षा' के लिए नौ-सदस्यीय कार्यसमूह के गठन की घोषणा की है। इस कार्यसमूह का प्रमुख आरबीआई के कार्यकारी निदेशक राधा श्याम राठो को बनाया गया है। समूह 30 अप्रैल, 2025 तक अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है। आरबीआई ने कहा कि यह समूह ट्रेडिंग समय और निपटान के संबंध में बाजारों के समग्र कामकाज में चुनौतियों की पहचान करेगा।

'यूरिया की देश में कोई किल्लत नहीं, कुछ लोग मुनाफाखोरी के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे पी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि देश में यूरिया खाद की कोई किल्लत नहीं है और कुछ लोग मुनाफाखोरी के लिए इसके दामों को प्रभावित कर परेशानी पैदा कर रहे हैं। नड्डा ने लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह भी कहा कि जन प्रतिनिधियों को और राज्य सरकार को इस तरह के तत्वों पर कार्रवाई करने में मदद करनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश के धौरहरा से समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने जब राज्य में यूरिया की किल्लत होने का दावा किया तो नड्डा ने कहा, ''यूरिया की किल्लत कभी नहीं रही। किल्लत पैदा की जाती है। कुछ लोग बाजार में सेंध लगाते हैं और अनावश्यक तरीके से मुनाफा कमाने के लिए इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं।'' उन्होंने सांसदों से भी अनुरोध किया कि इस स्थिति से निपटने में सहयोग करें।

नड्डा ने जनता दल (यूनाइटेड) की सदस्य लवली आनंद के एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि किसानों तक डीएपी उर्वरक की आपूर्ति समय पर करने के लिए एक तिथिवार, सप्ताह वार और क्षेत्रवार रणनीति बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि जहां तक डीएपी के वितरण का सवाल है तो इसमें अनावश्यक रूप से परेशानी पैदा करने वाले तत्वों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और केंद्र उनके संपर्क में रहता है। नड्डा ने कहा कि देश में यूरिया के 45 किलोग्राम के बोरे का एमआरपी 266 रुपए है और उस पर सरकार 1400 रुपए की सब्सिडी दे रही है, वहीं 50 किग्रा का डीएपी का बोरा किसानों को 1350 रुपए में दिया जाता है और इस पर भी सरकार 1650 रुपए की सब्सिडी दे रही है।

विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए साहसिक सुधार महत्वपूर्ण: नीति आयोग

नई दिल्ली/भाषा। नीति आयोग ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए साहसिक सुधार, टिकाऊ ऊर्जा रणनीति और वैश्विक व्यापार में नेतृत्वकारी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। भारत की वैश्विक व्यापार स्थिति को बढ़ाने के संभावित तरीकों के रूप में व्यापार उदारीकरण, शुल्क दर में कटौती और प्रौद्योगिकी सहयोग को संभावित उपायों के रूप में चिन्हित किया है। नीति आयोग के सम्मेलन में विशेषज्ञों ने यह बात कही। सम्मेलन का विषय 'विकसित भारत एट 2047: अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक भागीदारी और कानून को मजबूत बनाना' था।

सम्मेलन में शामिल विशेषज्ञों ने अनुसंधान व विकास, राजकोषीय मजबूती और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकरण को लेकर निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि की आवश्यकता बतायी। इसमें कहा, ''इस बात पर सहमति थी कि साहसिक सुधार, टिकाऊ ऊर्जा रणनीतियां और वैश्विक व्यापार में नेतृत्वकारी भूमिका 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।''

फोनपे 'खाता एग्रीगेशन' कारोबार से बाहर निकली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। देश की सबसे बड़ी वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) कंपनी फोनपे ने शुक्रवार को कहा कि वह 'खाता एग्रीगेशन' (एए) कारोबार से बाहर निकल गई है। कंपनी ने कहा कि वह उम्मीद के मुताबिक सेवाएं देने के लिए पर्याप्त साझेदार नहीं जोड़ सकी, इसलिए यह फैसला किया गया।

फोनपे ने कहा कि उसने आरबीआई को एनबीएफसी-एए लाइसेंस सौंपने का फैसला किया है, और वह एए संचालन को बंद कर देगी। एए लाइसेंस से कंपनी को उपयोगकर्ताओं की सहमति से उनकी वित्तीय जानकारी हासिल करने, और ऋण, क्रेडिट कार्ड जैसी वित्तीय सेवाएं देने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के साथ उसे साझा करने की अनुमति मिली थी।

फोनपे ने कहा, ''हमें गर्व है कि हम दो साल से भी कम समय में अपने एए मंच पर लगभग पांच करोड़ भारतीयों को पंजीकृत करने में कामयाब रहे हैं। हालांकि, प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं के कारण, हम अपने मंच पर उतने वित्तीय सूचना प्रदाताओं (एफआईपी) को शामिल नहीं कर पाए हैं, जितने हम चाहते थे। इसलिए फोनपे समूह ने खाता एग्रीगेटर व्यवसाय से बाहर निकलने का फैसला किया है। इसके बजाय हम बाजार में दूसरे एए के साथ साझेदारी करेंगे।'' वॉलमार्ट समूह की इस कंपनी को जून, 2023 में एए लाइसेंस मिला था। कंपनी ने कहा कि वह जल्द ही अपने एए उपयोगकर्ता आधार से संपर्क करेगी और उन्हें इस फैसले के बारे में बताएगी और नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप उनकी मदद करेगी।

अंतर-राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई-नाम मंच का उन्नयन किया जाएगा: चौहान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को संसद में कहा कि अंतर-राज्यीय और मंडी व्यापार में आने वाली साजो-सामान संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए केंद्र लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं को जोड़ने की सुविधा के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) मंच का उन्नयन करेगा। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि दिसंबर 2024 तक ई-नाम मंच पर 65.48 करोड़ रुपए मूल्य का 23,121 टन अंतरराज्यीय व्यापार दर्ज किया है।

चौहान ने कहा कि कृषि विपणन राज्य का विषय है और कृषि उपज मंडी समितियां (एपीएमसी) संबंधित राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम द्वारा विनियमित होती हैं। उन्होंने कहा, ''ऑनलाइन अंतर-राज्यीय व्यापार के लिए, अन्य राज्यों के व्यापार लाइसेंसों को मान्यता देने के लिए सक्षम प्रावधानों की आवश्यकता होती है।'' आठ राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपने एपीएमसी अधिनियमों में सक्षम प्रावधानों को शामिल किया है। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश ने भी अंतर-राज्यीय व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। चौहान ने कहा, ''इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ई-नाम के तहत अंतर-राज्यीय और अंतर-मंडी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स एक बड़ी बाधा बनी हुई है, सरकार ने ई-नाम प्लेटफॉर्म को ई-नाम 2.0 के रूप में उन्नयन करने का निर्णय लिया है।'' ई-नाम प्लेटफॉर्म को कुशल, उपयोगकर्ता के अनुकूल, समावेशी और ओपन-नेटवर्क के अनुपालन योग्य बनाया जाएगा। ई-नाम 2.0 की विशेषताएं बैंक खाता सत्यापन, आधार का उपयोग करते हुए ईकेवाईसी सुविधाएं और परख, लॉजिस्टिक्स और अन्य मूल्य वर्धित सेवा प्रदाताओं को शामिल करना होगा।

गोयल ने एआई के लिए मजबूत विनियामक ढांचे पर जोर दिया

नई दिल्ली/भाषा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के अनैतिक उपयोग को रोकने और इसका प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए कानूनी और नीतिगत समर्थन के साथ एक मजबूत नियामक ढांचा बनाने की जरूरत है। गोयल ने यह भी कहा कि प्रौद्योगिकी एक साधन बन सकती है, लेकिन कभी भी मानव मस्तिष्क की जगह नहीं ले सकती है। गोयल ने हितधारकों से कहा, ''हमें सही नियामक ढांचा बनाने के लिए मदद कीजिए। जरूरी नहीं कि इसमें केवल कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या पेटेंट से जुड़े मुद्दे ही हों, बल्कि कानून के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा मजबूत नियमन बनाएं, जो एआई के दुरुपयोग या अनैतिक उपयोग दोनों का सामना कर सके और जो आधुनिक प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग का भी समर्थन करे।'' उन्होंने यहां 'विधि प्रगति: राष्ट्रीय आईपी छात्र अदालत प्रतियोगिता, 2025' के उद्घाटन समारोह में कहा कि एआई और कॉपीराइट का विषय इस समय बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि एआई में आज लोगों के काम करने के तरीके को बाधित करने की पूरी क्षमता है।

एलआईसी का तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 17% बढ़कर 11,056 करोड़ रुपए पर

नई दिल्ली/भाषा। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का चालू वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 17 प्रतिशत बढ़कर 11,056 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी का गत वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में मुनाफा 9,444 करोड़ रुपए रहा था।

एलआईसी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि तिमाही के दौरान उसकी शुद्ध प्रीमियम आय घटकर 1,06,891 करोड़ रुपए रह गई, जो गत वित्त वर्ष की इसी अवधि में 1,17,017 करोड़ रुपए थी। कुल आय भी अक्टूबर-दिसंबर, 2024 में सालाना आधार पर 2,12,447 करोड़ रुपए से घटकर 2,01,994 करोड़ रुपए रह गई।

भारतीयों को अवैध रूप से अमेरिका भेजने वाले एजेंटों के 'जटिल नेटवर्क' की जांच कर रही ईडी

नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कनाडाई कॉलेजों में ''फर्जी'' दाखिले के जरिए भारतीयों को अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने में मदद करने वाले भारत, कनाडा और अमेरिका में एजेंटों तथा मददगारों के ''जटिल नेटवर्क'' की जांच कर रहा है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ईडी ने बताया कि 8,500 से अधिक मौद्रिक लेन-देन एजेंसी की जांच के दायरे में हैं और वह गुजरात पुलिस की अपराध शाखा की 2023 की प्राथमिकी का संज्ञान ले रही है।

यह कार्रवाई धन शोधन रोधी कानून के तहत दर्ज मामले में की गई है। अधिकारियों ने बताया कि विदेशों में धन भेजने में सहायता करने वाली कुछ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय कंपनियां भी ईडी की जांच के दायरे में हैं। एजेंसी ने पिछले एक वर्ष में 35 जगह छापेमारी कर 92 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। बुधवार को 104 निर्वासित भारतीयों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान के अमृतसर में उतरने के बाद यह मुद्दा संसद और संसद के बाहर चर्चा का केंद्र बन गया। ईडी ने पिछले वर्ष 24 दिसंबर को एक बयान जारी कर बताया था कि एजेंसी कनाडा की सीमा से भारतीयों की तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले में कुछ कनाडाई कॉलेजों और कुछ भारतीय संस्थाओं की कथित संलिप्तता की जांच कर रही है। यह जांच गुजरात के डिंगुचा गांव के रहने वाले चार सदस्यीय भारतीय परिवार की मौत से जुड़ी है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़े राहुल के आरोपों को भाजपा ने निराधार बताया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों को शुक्रवार को ''निराधार और ओछा'' करार दिया तथा कहा कि यह ''हारे हुए व्यक्ति के रोने'' से ज्यादा कुछ नहीं है। गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ इस तरह के झूठे और ओछे आरोप लगाने से उन्हें क्या हासिल होता है?''

भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी के आरोपों को लेकर उनकी आलोचना करते हुए इसे ''निराधार'' करार दिया। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''उनके आरोप निराधार हैं... एक हारे हुए व्यक्ति के रोने से ज्यादा कुछ नहीं।'' भाजपा नेता ने रेखांकित किया कि 18 जनवरी को गांधी ने कहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की मतदाता सूची में एक करोड़ मतदाता जोड़े गए। उन्होंने कहा, ''तीन फरवरी को संसद में उन्होंने दावा किया कि यह संख्या 70 लाख है। आज वह 39 लाख का नया नंबर लेकर आ गए। क्या विपक्ष के नेता को पता भी है कि वह क्या बोल रहे हैं?'' गांधी के दावे को ''झूठा और आधारहीन'' करार देते हुए महाराष्ट्र से भाजपा के राज्यसभा सदस्य भागवत कराड ने कहा कि लोगों ने राज्य में महायुति सरकार और केंद्र में नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के कारण विधानसभा चुनाव में महायुति को अपना जनादेश दिया। भाजपा नेता ने कहा, ''यदि ऐसा होता (यदि राहुल गांधी का दावा सही होता) तो हम हर जगह (सभी विधानसभा सीटों पर) विजयी होते।'' उन्होंने संसद परिसर में पीटीआई-भाषा के एक सवाल के जवाब में कहा, ''हम झारखंड विधानसभा चुनाव हार गए। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं।''

महाराष्ट्र की वयस्क आबादी से ज्यादा मतदाता, बात नहीं सुनी गई तो जाएंगे न्यायालय : राहुल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की मदाता सूची में 'विसंगतियां' हैं और बार-बार आग्रह के बावजूद निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश के मतदाताओं के डेटा उपलब्ध नहीं कराने से लगता है कि कुछ न कुछ गलत है।

राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या राज्य की कुल वयस्क आबादी से ज्यादा है। उन्होंने कहा, ''सरकार के आंकड़े के अनुसार, राज्य की वयस्क आबादी 9.54 करोड़ है, जबकि मतदाताओं की संख्या 9.70 करोड़ है।'' नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा में) ने शिवसेना (उबाठा) के नेता संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह भी कहा कि यदि निर्वाचन आयोग डेटा उपलब्ध कराने की मांग नहीं मानता को अगला कदम न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना होगा। उन्होंने

कहा कि निर्वाचन आयोग को पारदर्शिता लानी चाहिए, महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों से जुड़ी पूरे राज्य की केंद्रीकृत मतदाता सूची उपलब्ध कराना उसकी जिम्मेदारी है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या राज्य की कुल आबादी से अधिक होने के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर लिखित में पूरे तथ्यों के साथ जवाब देगा। राहुल गांधी ने कहा, ''हमारी टीम ने मतदाता सूची और मतदान पैटर्न का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और हम कुछ समय से इस पर काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हमें कई विसंगितयां मिलीं।'' उन्होंने कहा कि देश के लिए, विशेषकर युवा लोगों के लिए जो लोकतंत्र के पक्षधर हैं और उसमें विश्वास करते हैं, इन निष्कर्षों से अवगत होना और समझना आवश्यक है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि पिछले साल लोकसभा चुनाव और फिर पांच महीने बाद हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच की अवधि में राज्य में हिमाचल प्रदेश की आबादी के बराबर की संख्या में मतदाता बढ़ गए।''

उनके अनुसार, लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में पांच महीनों में 39 लाख मतदाता जुड़े, जबकि पिछले पांच वर्षों में 32 लाख मतदाता जुड़े थे। उन्होंने सवाल किए कि ये मतदाता कहां से आए हैं और ये कौन हैं?

न्यायपालिका तक पहुंच को 'हथियार' बनाया जा रहा है : जगदीप धनखड़

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि न्यायपालिका तक पहुंच को इस तरह से 'हथियार' बनाया गया है, जो दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं हो रहा है। देश के भीतर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयासों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, सबसे पुराने लोकतंत्र, सबसे मजबूत लोकतंत्र, सबसे प्रगतिशील लोकतंत्र और सबसे जीवंत लोकतंत्र वाले देश में - और संवैधानिक रूप से दुनिया का एकमात्र देश जिसमें हर स्तर पर लोकतांत्रिक प्रणाली है, चाहे वह गांव हो, शहर हो, राज्य हो या राष्ट्र हो - हमारी चुनावी प्रक्रिया को इस तरह से प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए।

वह हावेरी जिले के राणेबेन्नूर में आयोजित कर्नाटक वैभव साहित्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव के तीसरे संस्करण के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। धनखड़ ने कहा कि विभाजनकारी ताकतें अलग-अलग तरीकों से काम करती हैं। धनखड़ ने कहा, इन ताकतों ने नये-नये रास्ते अपनाए हैं और बहुत से मुद्दों पर आप देखेंगे कि वे न्यायपालिका की शरण में जाते हैं।

उन्होंने दावा करते हुए कहा, मैं चिंतित हूं, क्योंकि हमारे देश के संविधान ने न्यायिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को अधिकार दिया है। और वह अधिकार क्या है? न्यायालय की शरण लेने का अधिकार। हालांकि, हाल के वर्षों में, राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए धन का इस्तेमाल किया गया है, और न्यायपालिका तक पहुंच को हथियार बनाया गया है, और यह इस तरीके से हो रहा है, जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, राष्ट्र को चुनौती देने वाली, जो राष्ट्रवाद एवं क्षेत्रवाद के बीच टकराव पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें बहुत करारा जवाब मिलना चाहिए। वे हमारी सांस्कृतिक विरासत को कमजोर करना चाहते हैं। राष्ट्र के सांस्कृतिक दर्शन को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए धनखड़ ने कहा, आज के दिन, जब मैं एक तरफ देखता हूं, तो भारत की प्रगति को दुनिया की नजर से देखना चाहिये, राष्ट्र के अंदर बसने वाले लोगों की नजर से देखो, तो वो बारिश में नाचते हुए मोर के पंख की तरह हैं...लेकिन जब मैं मोर के पैरों को देखता हूं, तो मुझे चिंता होती है, सोचने पर मजबूर हो जाता हूं और फिर मुझे अपने सांस्कृतिक दर्शन की आवश्यकता महसूस होती है। हम उसी शाखा को काटने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर हम पनप रहे हैं, जिस पर हम बैठते हैं।

उन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, आईएमएफ (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष), विश्व बैंक और दुनिया की अन्य अग्रणी संस्थाएं कहती हैं कि अगर निवेश, अवसरों और प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए दुनिया में कोई चमकता सितारा है, तो वह भारत है। भारत को निवेश और अवसरों के लिए वैश्विक पसंदीदा गंतव्य माना जाता है।

सिद्दरामय्या को राहत, एमयूडीए मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से उच्च न्यायालय का इनकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या को राहत देते हुए सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने एमयूडीए भूमि आवंटन मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया था। सिद्दरामय्या मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 14 भूखंड आवंटित किए जाने में अनियमितताएं बरते जाने के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

स्नेहमयी कृष्णा ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि सिद्दरामय्या मुख्यमंत्री होने के नाते राज्य के विभागों, विशेषकर पुलिस प्राधिकारियों और कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस जैसी राज्य की जांच एजेंसियों पर अत्यधिक प्रभाव रखते हैं, ऐसे में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लोकायुक्त कार्यालय की स्वतंत्रता पर कोई प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने कहा, मामले से संबंधित दस्तावेजों से कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता कि लोकायुक्त द्वारा की गई जांच पक्षपातपूर्ण, एकतरफा या कमजोर है, जिसके कारण इस अदालत को मामला विस्तृत जांच या फिर से जांच के लिए सीबीआई को सौंपना पड़े....याचिका खारिज की जाती है।

लोकायुक्त पुलिस ने सिद्दरामय्या, उनकी पत्नी, रिश्तेदार बी. एम. मल्लिकार्जुन स्वामी, देवराजू (जिनसे स्वामी ने एक भूखंड खरीदकर पार्वती को उपहार में दिया था) तथा अन्य को मैसूरु में 27 सितंबर को दर्ज की गई प्राथमिकी में नामजद किया था। यह प्राथमिकी पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों से संबंधित विशेष अदालत के आदेश के बाद दर्ज की गई थी।

न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने तीन प्रश्नों पर विचार किया – क्या लोकायुक्त कार्यालय की स्वतंत्रता संदिग्ध है; किन परिस्थितियों में संवैधानिक न्यायालयों ने जांच, विस्तृत जांच, पुनः जांच सीबीआई को सौंपी, किन मामलों को सौंपने से इनकार दिया; और क्या लोकायुक्त द्वारा की गई जांच के संबंध में उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर मामले को विस्तृत जांच या पुनः जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए।

नागप्रसन्ना ने कहा, इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा बताई गई ऐसी कोई खामी नहीं है, जिसके कारण मामले को विस्तृत जांच या पुनः जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाए।

एमयूडीए मामला: उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे याचिकाकर्ता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मैसूरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज किए जाने के बाद मामला दर्ज करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने शुक्रवार को कहा कि वह इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या पर एमयूडीए द्वारा उनकी पत्नी पार्वती बी. एम. को उनसे अधिग्रहित भूमि के बदले में रिहायशी इलाके में 14 स्थल आवंटित करने में अनियमितता के आरोप हैं।

कृष्णा ने कहा, यह मेरी लड़ाई में एक झटका है, लेकिन मेरे विचलित होने या अपनी लड़ाई से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हम उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करेंगे और मामला सीबीआई को सौंपने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, जिन आधारों पर उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की है, उनके मद्देनजर हम अपने वकीलों से इस बारे में चर्चा करेंगे कि इस पर क्या जवाब दिया जाए और जरूरी दस्तावेज भी साथ लेकर जाएं। हम इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे और सीबीआई जांच का अनुरोध करेंगे।उन्होंने कहा, हमने उच्च न्यायालय को यह समझाने की कोशिश की कि लोकायुक्त पुलिस आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, लेकिन हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि उच्च न्यायालय ने किस आधार पर आदेश दिया है। उसके आधार पर हम मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का प्रयास करेंगे। अपनी याचिका में स्नेहमयी कृष्णा ने दलील दी है कि निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते सिद्दरामय्या राज्य के विभागों, विशेष रूप से राज्य की जांच एजेंसियों जैसे पुलिस अधिकारियों और कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस पर बहुत अधिक प्रभाव रखते हैं।

पूर्व एवं निर्वाचित सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों को देखने वाली विशेष अदालत के आदेश के बाद सिद्दरामय्या, उनकी पत्नी, बहनोई बी. एम. मल्लिकार्जुन स्वामी, देवराजू – जिनसे स्वामी ने एक जमीन खरीदी थी और इसे पार्वती को उपहार में दिया था और अन्य को 27 सितंबर को मैसूरु स्थित लोकायुक्त पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में नामित किया गया है। कृष्णा ने कहा कि लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर जांच सही दिशा में हो रही है, इसलिए उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि आदेश मिलने के बाद, इसमें मौजूद खामियों के आधार पर तुरंत सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त की जांच के एकतरफा होने का संदेह है और इसके सबूत भी हैं।

येडीयुरप्पा को उच्च न्यायालय ने दी जमानत, मामले को निचली अदालत में भेजा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येडीयुरप्पा की याचिका शुक्रवार को आंशिक रूप से स्वीकार कर ली जबकि उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को वापस निचली अदालत के पास भेज दिया। अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। येडीयुरप्पा (81) ने भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत अपने खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को रद्द करने का अनुरोध किया था।

मामला पिछले साल 14 मार्च को 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि येडीयुरप्पा ने दो फरवरी को यहां डॉलर्स कॉलोनी में स्थित अपने आवास पर मुलाकात के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था। येडीयुरप्पा के खिलाफ एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही सीआईडी ङ्घङ्घने पिछले साल 27 जून को त्वरित सुनवाई अदालत के समक्ष दायर आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि उन्होंने और तीन अन्य आरोपियों ने कथित पीड़िता और उसकी मां को चुप रहने के लिए पैसे दिए थे।

अन्य तीन सह-आरोपी हैं अरुण वाई एम, रुद्रेश एम और जी मारिस्वामी। इन्हें येडीयुरप्पा का करीबी माना जाता है। येडीयुरप्पा के खिलाफ आरोप लगाने वाली पीड़िता की 54 वर्षीय मां की पिछले साल मई में फेफड़ों के कैंसर के कारण यहां एक निजी अस्पताल में मौत हो गई थी।

कर्नाटक सरकार का शोध में सहयोग के लिए लिवरपूल यूनिवर्सिटी के साथ समझौता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक सरकार ने शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ब्रिटेन की लिवरपूल यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि समझौता ज्ञापन राज्य और ब्रिटिश विश्वविद्यालय के बीच शोध एवं शैक्षणिक संबंधों को मजबूती देगा।

एमओयू पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित कार्यक्रम में कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व भारी और मध्यम उद्योग मंत्री एम बी पाटिल, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव एस सेल्वाकुमार और औद्योगिक विकास आयुक्त गुंजन कृष्णा ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या भी मौजूद थे।

बयान के मुताबिक, यह साझेदारी वैश्विक स्तर पर कर्नाटक की शैक्षणिक और अनुसंधान साझेदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें कहा गया, इस सहयोग का उद्देश्य ज्ञान के आदान-प्रदान को आगे बढ़ाना, शैक्षणिक गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना और संयुक्त अनुसंधान पहलों का समर्थन करना है। इससे संस्थानों और उद्योग हितधारकों, दोनों को लाभ होगा।

इस समझौते को ब्रिटेन के उप-उच्चायोग में ब्रिटिश काउंसिल प्रकोष्ठ की निदेशक जनक पुष्पनाथन, मिशन उप प्रमुख जेम्स गोडबर और लिवरपूल यूनिवर्सिटी के कुलपति टिम जोन्स सहित प्रमुख व्यक्तियों की भागीदारी के साथ औपचारिक रूप दिया गया। बयान के मुताबिक, यह समझौता ज्ञापन उन्नत अनुसंधान और विकास पहल, छात्र और संकाय विनिमय कार्यक्रमों और मजबूत उद्योग-अकादमिक संबंधों का रास्ता खोलेगा। यह उच्च शिक्षा और नवाचार में वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे ज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में राज्य की स्थिति और मजबूत होगी।

इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर्नाटक के वैश्विक निवेशक सम्मेलन 'इन्वेस्ट कर्नाटक 2025' से पहले हुए हैं। इस निवेश सम्मेलन का आयोजन 12-14 फरवरी, 2025 को किया जाएगा।

तमिलनाडु में कंपनी ने कर्मचारियों को 14.5 करोड़ रुपये का बोनस दिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोयंबटूर। तमिलनाडु स्थित सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस (एसएएएस) कंपनी कोवाई.को ने उनकी सेवाओं का 'सम्मान' करते हुए अपने 260 कर्मचारियों में से लगभग 140 को लगभग 14.5 करोड़ रुपये का बोनस देने की पेशकश की है।

जो कर्मचारी 31 दिसंबर, 2022 को या उससे पहले शहर स्थित कंपनी में शामिल हुए हैं, उन्हें तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर उनके सकल वार्षिक वेतन का 50 प्रतिशत बोनस के रूप में मिलेगा। कोवाई.को ने कंपनी के मुनाफे को अपने कर्मचारी आधार के साथ साझा करने के लिए 2022 में सभी मौजूदा और नए कर्मचारियों के लिए 'टुगेदर वी ग्रो' बोनस पेश किया है। कंपनी कोयंबटूर के अलावा लंदन और चेन्नई में भी उपस्थित है।

कंपनी ने कहा कि तदनुसार, लाभार्थियों के पहले जत्थे में से लगभग 80 लोगों को जनवरी के वेतन के हिस्से के रूप में बोनस मिलेगा। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और संस्थापक सरवन कुमार ने कहा, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कंपनी की सफलता और मुनाफे में योगदान देने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। धन साझा करने और वितरित करने के तरीके खोजना भी मेरा सपना रहा है। कुमार ने कहा कि बोनस विकल्प के साथ आने से पहले वे कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए अन्य वैकल्पिक विकल्पों पर विचार कर रहे थे।

उन्होंने बयान में कहा, हमने कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना या शेयरों पर विचार किया। लेकिन यह 'कागजी मुद्रा' है जो तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक कंपनी बाहरी पूंजी नहीं जुटाती या अपने शेयरों को सूचीबद्ध करने का निर्णय नहीं लेती। उन्होंने कहा कि कंपनी ने नकद पुरस्कार देने का विकल्प चुना है, ताकि उसके कर्मचारी इसका उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकें।

अचानक हुई मौतों और कोविड-19 के बीच संबंध की पड़ताल के लिए समिति गठित हो : सिद्दरामय्या

बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने अधिकारियों को राज्य में दिल के दौरे और मस्तिष्क संबंधी समस्याओं के कारण अचानक होने वाली मौतों पर गहन अध्ययन के लिए विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है और यह पड़ताल करने का निर्देश दिया है कि क्या इनका कोई संबंध कोरोना वायरस या कोविड-19 टीकों के दुष्प्रभावों से है।

बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक नोट में कहा गया, वरिष्ठ पत्रकार राजाराम तल्लूर ने हमें ईमेल के माध्यम से बताया है कि हाल में दैनिक समाचार पत्रों में छपी खबरों में राज्य में हृदयाघात, मस्तिष्क संबंधी समस्याओं, तंत्रिका संबंधी विकारों और अन्य कारणों से युवाओं की अचानक मृत्यु की खबरें सामने आई हैं।

राज्यपाल ने सरकार के प्रस्तावित माइक्रोफाइनेंस अध्यादेश को खारिज किया

बेंगलूरु। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्दरामय्या के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा 'माइक्रोफाइनेंस' को विनियमित करने के लिए लाये गये 'कर्नाटक माइक्रो फाइनेंस' (जबरदस्ती कार्रवाई की रोकथाम) अध्यादेश 2025 को शुक्रवार को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, राज्यपाल ने अध्यादेश को नामंजूर करने के कई कारण बताए हैं। कार्यालय ने बताया कि गहलोत को लगा कि कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित 10 वर्ष की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना अत्यधिक है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि उनका (राज्यपाल का) यह भी मानना है कि मौजूदा कानूनों का इस्तेमाल पुलिस विभाग द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता था। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, राज्यपाल द्वारा दिया गया दूसरा कारण यह है कि अध्यादेश का 'माइक्रोफाइनेंस' पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है और इसका असर अंततः गरीबों पर पड़ेगा। माइक्रोफाइनेंस संस्थानों द्वारा उधारकर्ताओं को उत्पीड़न से बचाने के उद्देश्य से, कर्नाटक सरकार ने दंडात्मक प्रावधानों के साथ अध्यादेश का मसौदा तैयार किया है, जिसमें उल्लंघन के लिए 10 वर्ष तक की जेल की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना शामिल है।

पदयात्रा

संवैधानिक मान्यता और सांस्कृतिक संरक्षण की मांग को लेकर फेडरेशन ऑफ कोडवा समाज द्वारा आयोजित 'कोडवमे बालो पदयात्रा' शुक्रवार को मदिकेरी पहुंची।

मुख्यमंत्री के विधि सलाहकार ने कहा - सिद्दरामय्या कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे

बेंगलूरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा एमयूडीए भूमि आवंटन मामले को सीबीआई को सौंपने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज करने पर खुशी व्यक्त करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता और मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार ए एस पोनन्ना ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की प्रतिबद्धता जताई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या को राहत देते हुए सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने एमयूडीए भूमि आवंटन मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया था। सिद्दरामय्या मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 14 भूखंड आवंटित किए जाने में अनियमितताएं बरते जाने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक पोनन्ना ने कहा, मैंने फैसले और उसकी विषय-वस्तु को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया है, उन्होंने खुशी जाहिर की है।

मलेशिया जाने वाला विमान 'आपातकालीन स्वास्थ्य स्थिति' के कारण चेन्नई में उतरा

चेन्नई। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर जाने वाले एक अंतरराष्ट्रीय विमान को 'आपातकालीन स्वास्थ्य स्थिति' के कारण चेन्नई में शुक्रवार को उतरना पड़ा। हवाई अड्डे के आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि ओमान के मस्कट से आ रहे विमान के एक यात्री ने बेचैनी की शिकायत की, जिसके बाद विमान के पायलट ने चेन्नई हवाई अड्डे के अधिकारियों से संपर्क किया और विमान को यहां उतारने की अनुमति देने का अनुरोध किया। उन्होंने अधिक जानकारी न देते हुए बताया कि अपराह्न करीब दो बजे विमान यहां उतरा, जिसके तुरंत बाद मेडिकल टीम मौके पर पहुंची।

दक्षिण पश्चिम रेलवे
निविदा सूचना सं: 41 UBL 2024-25
दिनांक: 31.01.2025
भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं:

कार्य का नाम	अनुमानित लागत
हुबली विभाग: हुबली में 18 महीने की निर्दिष्ट अवधि के लिए एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 1000 किलोग्राम क्षमता के बायोगैस संयंत्र की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग, साथ ही घर-घर जाकर कचरा संग्रहण और घरों से कचरे को अलग करने सहित संचालन और रखरखाव।	रु. 1,94,56,648.00

निविदाओं जमा करने की अंतिम तिथि: 28.02.2025, 11:00 बजे तक
विवरण के लिए लॉग ऑन करें www.ireps.gov.in में
वरिष्ठ विभागीय इंजीनियर/समन्वय हुबली
PUB/762/AAMO/PRB/SWR/2024-25
South Western Railway - SWR | SWRRLY | SWRRLY

राज्यपाल के अभिभाषण के बहस पर जवाब में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर किया हमला, विपक्ष ने फोन टैपिंग बंद करो के लगाए नारे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का नया अध्याय लिखा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस के हंगामे के बीच राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब दिया और विपक्ष को कठघरे में खड़ा किया। खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के न बोलने को लेकर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए इसे पार्टी की अंदरूनी कलह करार दिया। हंगामे के बीच विपक्षी विधायक नारे फोन टैपिंग बंद करो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाते रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर वंचित वर्ग से आने वाले नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोका, जिससे साफ जाहिर होता है कि पार्टी के भीतर गहरी खींचतान चल रही है। सत्ता पक्ष के इस आरोप से एक ओर जहां कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर सवाल उठते हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी स्पष्ट होता है कि भाजपा इस मुद्दे को एक बड़े चुनावी नैरेटिव के रूप में देख रही है।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार और धीमी गति का आरोप लगाया। यह बयान स्पष्ट करता है कि भाजपा आने वाले समय में कांग्रेस शासन की नाकामियों को जोर-शोर से उठाकर खुद को मजबूत स्थिति में लाने की रणनीति अपना रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह दावा कि चार साल बाद कांग्रेस विधायक सदन में नजर नहीं आएंगे, यह दिखाता है कि भाजपा अपने चुनावी भविष्य को लेकर बेहद आत्मविश्वास से भरी हुई है। हालांकि, यह दावा करना जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस पूरी तरह हाशिए पर चली जाएगी, लेकिन विधानसभा में मौजूदा गतिरोध और कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को देखते हुए भाजपा के लिए यह अवसर जरूर है कि वह अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करे।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि मोरिया किसका बोला? यानी उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस की हार की ओर इशारा करते हैं। इससे साफ है कि भाजपा राजस्थान में उपचुनाव के परिणामों को कांग्रेस के खिलाफ बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करने जा रही है।

मुख्यमंत्री का यह बयान कि डोटासरा के चक्कर में आ गए जूली, यह दर्शाता है कि भाजपा विपक्षी एकता को तोड़ने और कांग्रेस में अंतर्विरोध को उजागर करने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं, कांग्रेस के लिए यह जरूरी होगा कि वह अपनी गुटबाजी को खत्म कर एक संगठित विपक्ष की भूमिका निभाए, वरना भाजपा अपने राजनीतिक एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी।

मंत्री के फोन टैपिंग मामले पर कांग्रेस का विधानसभा में हंगामा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को विपक्षी कांग्रेस के विधायकों ने प्रदेश सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के कथित तौर पर फोन टैप किए जाने के मुद्दे पर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही यह मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि मंत्री का फोन टैप किया जा रहा है और मंत्री ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है। जूली ने कहा, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस विधायक शुक्रवार को सदन में काली पट्टी बांधकर पहुंचे और कथित फोन टैपिंग के मुद्दे को लेकर आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते रहे।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस विधायकों की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह चोरों का समूह है और विपक्ष का इस तरह का व्यवहार गलत है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधायकों से प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी रखने को कहा, लेकिन कांग्रेस विधायक आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने लगे।

विधानसभा अध्यक्ष ने इस वजह से सदन की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बाद में कांग्रेस विधायक सदन से बाहर आ गए और विधानसभा की सीढ़ियों पर नारेबाजी करने लगे। जूली ने संवाददाताओं से कहा, जब तक मुख्यमंत्री सदन में जवाब नहीं देते, हम सदन की कार्यवाही नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, यह बहुत बड़ा मुद्दा है राज्य के केबिनेट मंत्री का फोन टैप सरकार करा रही है?... इससे ज्यादा क्या हो सकता है? सरकार जवाब देने के लिये तैयार नहीं है।

हमने कह दिया है जब तक इस बात पर गृहमंत्री या मुख्यमंत्री का जवाब नहीं आयेगा, सदन नहीं चलेगा। सदन में राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर शुक्रवार को बहस का आखिरी दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष तथा उसके बाद मुख्यमंत्री अपने विचार रखेंगे। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया।

उन्होंने जयपुर के आमागढ़ मंदिर में बृहस्पतिवार को कार्यक्रम में सरकार को घेरा और कहा कि वह डरने वाले नहीं हैं। इससे पहले अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार में भी इस तरह के आरोप लगे थे। विधानसभा के बाहर कांग्रेस की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद अब कुछ नहीं बचा है। डोटासरा ने कहा, या तो मुख्यमंत्री जवाब देकर कैबिनेट मंत्री की छुट्टी करें और ये आरोप नकारे... और या मुख्यमंत्री त्यागपत्र दें.. दो ही बात हो सकती है तीसरी कोई बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जब तक स्पष्ट बयान नहीं आता, तब तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा।

फोन टैपिंग के आरोप लगाना उजागर करता है भाजपा की सच्चाई : गहलोत

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर अपने ही कैबिनेट मंत्री द्वारा फोन टैपिंग के आरोप लगाना भाजपा की सच्चाई को उजागर करता है। गहलोत ने शुक्रवार को अपने बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा हमारी सरकार के समय मैंने सदन के पटल पर कहा था कि किसी भी मंत्री, सांसद और विधायक का टेलिफोन सर्विलांस पर नहीं लिया गया और न ही लिया जाएगा। परन्तु भाजपा सरकार पर अपने ही कैबिनेट मंत्री द्वारा फोन टैपिंग के आरोप लगाना भाजपा की सच्चाई उजागर करता है।

उन्होंने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर प्रकृति का है क्योंकि आरोप राजनीतिक लाभ के लिए किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि सरकार के कैबिनेट मंत्री ने लगाए हैं।

किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर लगाया जासूसी का आरोप, राजेंद्र राठौड़ बोले ये चिंताजनक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर । राजस्थान सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर मंत्रियों के कॉल रिकॉर्डिंग करने और सीआईडी लगाने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने मीणा के इस बयान को चिंताजनक बताया। भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि किरोड़ी लाल पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अगर पुलिस तंत्र उन पर निगरानी रखता है, अगर निजी या कई अन्य कारणों से उन पर निगरानी की जा रही है तो वो गलत बात नहीं है। मेरा मानना है कि उनका बयान चिंताजनक जरूर है। उन्होंने किस संदर्भ में ऐसा बयान दिया, इसका खुलासा वो स्वयं ही कर सकते हैं। बाकी मुझे विश्वास है कि सरकार इस तरह का कुछ काम नहीं कर रही होगी।

किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। वो सड़क पर उतर कर आंदोलन करने के लिए जाने जाते हैं। गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने आवाज बुलंद की थी। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार बनने से पहले उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे, उस वक्त हम भी उनके साथ थे। उन सभी मुद्दों पर हम भी सहभागी थे। सरकार ने अलग-अलग योजना बनाकर उन मुद्दों पर काम किया। प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है। मेरे हिसाब से भाजपा जिन मुद्दों पर सरकार में आई है, उस पर काम कर रही है।

बता दें, राजस्थान सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि मैं निराश हूं कि जो आंदोलन हमने किया, जिसकी वजह से हम सत्ता में आए, अब उन मुद्दों पर काम नहीं हो रहा है। उन मुद्दों को भुला दिया गया है। किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार पर मंत्रियों के कॉल रिकॉर्डिंग और उनके पीछे सीआईडी लगाने का भी आरोप लगाया है।

ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दंपति की मौत

जयपुर। राजस्थान के अलवर में शुक्रवार सुबह ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दंपति की मौत हो गई और एक अन्य युवती घायल हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना सुबह 10 बजे वैशाली नगर थाना क्षेत्र में नमन होटल के पास हुई।

वैशाली नगर थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि हादसे में कासम खान (40) और उनकी पत्नी सहिला खान (40) की मौत हो गई और कासम की बहन जुबैदा घायल है। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि होटल के पास के सभी सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है।

किरोड़ी लाल मीणा बोले, सरकार मेरी जासूसी कर रही, फोन टैप हो रहा, मैं डरता नहीं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर जासूसी करने और फोन टैप करने का संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार के कुछ मामले बीच में उठाए थे। 50 फर्जी थानेदारों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने जब कहा कि ये परीक्षा रद्द करो, तो सरकार ने मेरी बात नहीं मानी। उल्टा सरकार की तरफ से जैसा पिछले राज में हुआ करता था, वैसा ही हो रहा है। चप्पे-चप्पे पर मेरे लिए सीआईडी लगाई जा रही है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। डॉ. मीणा ने कहा कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।

गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान विधानसभा में कहा था कि समय मिलावट का है और हां में हां करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। हां जी के दरबार में जो ना जी कहेगा तो मरेगा। मेरी हां कहने की आदत नहीं है, लेकिन जो कहता हूं, सच कहता हूं। मुझे इस बात का दर्द है। मीडिया से चर्चा के दौरा किरोड़ी लाल मीणा का दर्द छलक पड़ा था। उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में विपक्ष की भूमिका किसने निभाई? मुझे पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता भी नहीं करने दी गई, लेकिन मैं सड़क खड़ा रहा। उसके आधार पर हम सत्ता में आए। जब मुद्दे मरते हैं और परिणाम नहीं निकलता है तो मैं भी मुरझा जाता हूं और दुख होता है।

श्रद्धांजलि

उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने शुक्रवार को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के निजी आवास पर पहुंचकर उनके पिता स्व. कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़ की पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि करती हुई।

बैंकॉक से आई फ्लाइट में सांप-बिच्छू की तस्करी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक चौंकाने वाला मामला पकड़ा है। बैंकॉक से आई फ्लाइट में दो संदिग्ध यात्री खतरनाक जीवों की तस्करी कर रहे थे। जब उनकी तलाशी ली गई तो सात प्लास्टिक के डिब्बों में विभिन्न प्रजातियों के सांप, मकड़ियां और बिच्छू मिले। जांच में सामने आया कि इन जीवों को नशे के लिए इस्तेमाल किया जाना था। नशे के लिए सांपों और बिच्छुओं का उपयोग करना किसी हॉलीवुड फिल्म की साजिश जैसा लगता है, लेकिन यह वास्तविकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, कई देशों में 'स्नेक बाइट' ड्रग का चलन बढ़ रहा है, जिसमें जहरीले सांपों का जहर या उनके काटने से उत्पन्न रसायनों का उपयोग किया जाता है।

नशेड़ी लोग सांप को पकड़कर खुद को डसवाते हैं। शुरू में हाथ की उंगली या पैर के अंगूठे में डसवाया जाता है, फिर धीरे-धीरे होठ, कान और जुबान तक पहुंच जाते हैं। कोबरा और अन्य जहरीले सांपों के जहर को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है, जिसे ड्रिंक्स में मिलाकर लिया जाता है।

कुछ लोग सांप को बोतल में बंद करके उसके डंक से अपना नशा पूरा करते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में नशे के लिए कोबरा (नाजा नाजा), कॉमन क्रेट (बुंगारस कैर्यूलस) और हरा सांप (ओफियोड्रिस वर्नालिस) का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। दोनों आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उन्हें इस खेप की असली सच्चाई की जानकारी नहीं थी। हालांकि, कस्टम विभाग और वन विभाग इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं। यह मामला दर्शाता है कि ड्रग्स की दुनिया में नए और खतरनाक तरीके अपनाए जा रहे हैं। पहले जहां नशीले पदार्थों की तस्करी पारंपरिक ड्रग्स तक सीमित थी, अब जीवित प्राणियों को भी इस काले बाजार का हिस्सा बनाया जा रहा है।

राज्य में भू-जल स्तर बढ़ाने के हो रहे सार्थक प्रयास : कन्हैया लाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। भू-जल मंत्री कन्हैया लाल ने कहा कि राज्य सरकार भू-जल स्तर बढ़ाने व वर्षाजल संरक्षण करने के लिए प्रभावी कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक को अटल भू-जल योजना में जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि राज्य के भू-जल संसाधनों की नवीनतम आकलन रिपोर्ट वर्ष-2024 में 295 पंचायत समितियों तथा 7 शहरी क्षेत्रों सहित कुल 302 इकाइयों का आंकलन किया गया है। जिसमें 214 इकाइयां अतिदोहित, 27 इकाइयां संवेदनशील, 21 इकाइयां अर्द्धसंवेदनशील, 37 इकाइयां सुरक्षित तथा 3 इकाइयां लवणीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीक्रत हैं। उन्होंने बताया कि राज्य की भू-जल दोहन दर 149.86 प्रतिशत रही है।

भू-जल मंत्री शुक्रवार को प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2023 के दौरान वर्षा जल संरक्षण हेतु भू-जल पुनर्भरण के प्रचलित तकनीकी उपायों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कृत्रिम भू-जल संचरनाओं का निर्माण करवाया गया। इसी कारण भीलवाड़ा के भू-जल परिदृश्य में सकारात्मक परिणाम दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए कार्यों के परिणामस्वरूप भीलवाड़ा की 12 पंचायत समितियों में से 7 पंचायत समितियों आसीन्द, बिजोलिया, जहाजपुर, कोटड़ी, मांडलगढ, शाहपुरा और सुवाणा में औसत भू-जल स्तर में बढोतरी दर्ज की गई। उन्होंने भीलवाडा की पंचायत समितियों की औसत भूजल स्तर की विस्तृत रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी।

इससे पहले विधायक गोपीचन्द मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 के दौरान भीलवाडा में भू-जल स्तर बढ़ाने व वर्षाजल संरक्षण करने के लिए जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के समन्वय से कार्य किया गया। जिसमें विभिन्न योजनाओं के तहत फार्म पोण्ड, जल संरक्षण संरचनाऐं, परकोलेशन टैंक, संकन टैक, एनिकट इत्यादि का निर्माण अथवा पुनरुद्धार किया गया।

अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले में राजस्थान पवेलियन हुआ शुरू, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने किया सूरजकुंड मेले का शुभारंभ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। हरियाणा के फरीदाबाद में शुक्रवार केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत ने 38 वें अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान श्री शेखावत ने मेले में राजस्थान पैवेलियन का दौरा किया। श्री शेखावत ने राजस्थान पवेलियन में लगे यूनेस्को हैरिटैज मोनिमेंट्स की तारीफ की। सूरजकुंड मेले में 7 से 23 फरवरी तक आयोजित होने वाले मेले में रात के समय 18 लाइव इवेंट्स होंगे। शनिवार को राजस्थान के लोक कलाकार मामे खान का इवेंट रहेगा। इस बार सूरजकुंड मेले में 42 देशों के 648 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे. ओडिशा और मध्य प्रदेश इस बार मेले के दो थीम राज्य हैं। सूरजकुंड मेला दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला बन चुका है, जो भारत की समृद्ध कला परंपराओं को संजोए हुए है।1987 में शुरू हुआ ये शिल्प मेला कारीगरों को सीधा बाजार उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका को सशक्त बनाने और भारत सरकार के वोकल फॉर लोकल तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये मेला छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करता है। मेला विशेषतौर पर महिला उद्यमियों को उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद रहा है. जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलता है।

चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरा जाएगा : दिलावर

जयपुर/दक्षिण भारत। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा है कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर प्राथमिकता से भरा जाएगा। दिलावर प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने आवश्यकता का आकलन किये बिना मनमर्जी तरीके से विद्यालय खोले। उन्होंने बताया कि चार हजार से ज्यादा विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें पद ही स्वीकृत नहीं किये और जो पद स्वीकृत हुए उन्हें भरा नहीं गया। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हिन्दी माध्यम के विद्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का बोर्ड चिपका दिया। इससे हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों के बच्चों का भविष्य अनिश्चितता में लटक गया। इसी प्रकार कई बालिका विद्यालयों को भी बदलकर अंग्रेजी माध्यम में बदल दिया।

इसके चलते बालिकाओं को स्कूल छोड़कर दूर-दराज की स्कूल में दाखिला लेना पड़ा या पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विद्यालय के बारे में जानकारी लेकर समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।

मुलाकात

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शुक्रवार को राजभवन में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल बागड़े ने उनका राजभवन में अभिनंदन किया। राज्यपाल से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

प्रयागराज महाकुंभ नगर में लगेगी सम्राट हर्षवर्धन की विशाल प्रतिमा

महाकुंभ नगर (उप्र)/भाषा। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में सम्राट हर्षवर्धन की विशाल प्रतिमा लगाई जाएगी। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इन्द्रेश कुमार ने बौद्ध महाकुंभ यात्रा के समापन अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष यह बात कही।

इन्द्रेश कुमार ने कहा, ''सम्राट हर्षवर्धन महादानवीर थे। वह प्रत्येक कुंभ में आकर अन्नदान एवं वस्त्रदान करते थे। सम्राट हर्षवर्धन हिंदू थे। विश्व को करुणा एवं मैत्री का संदेश देने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। संपूर्ण समाज उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है इसलिए प्रयागराज में उनकी भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी।''

अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखने वाले विहिप नेता कामेश्वर चौपाल का निधन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जताया शोक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/लखनऊ (उप्र)/भाषा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए पहली ईंट रखने वाले विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेता कामेश्वर चौपाल का बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मीडिया सेंटर की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, उन्होंने दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में अंतिम सांस ली। चौपाल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें ''भगवान राम का अनन्य भक्त'' बताया। मोदी ने एक्स' पर लिखा, भाजपा के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे एक अनन्य रामभक्त थे, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया।

प्रधानमंत्री ने लिखा, दलित पृष्ठभूमि से आने वाले कामेश्वर जी समाज के वंचित समुदायों के कल्याण के कार्यों के लिए भी हमेशा याद किए जाएंगे। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति! मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि पटना के रहने वाले चौपाल लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे।

ट्रस्ट के अनुसार, उन्होंने नौ नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम शिलान्यास समारोह में पहली ईंट रखी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने उन्हें 'प्रथम कारसेवक' की उपाधि से सम्मानित किया था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौपाल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, ''विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य और नौ नवंबर 1989 को आयोजित ऐतिहासिक शिलान्यास समारोह में पूज्य संत गण की उपस्थिति में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की प्रथम शिला रखने वाले परम राम भक्त श्री कामेश्वर चौपाल जी का निधन अत्यंत दुःखद है।'' मुख्यमंत्री ने कहा, ''उनका पूरा जीवन धार्मिक और सामाजिक कार्यों में समर्पित रहा। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति!

विश्व हिंदू परिषद ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से किए गए पोस्ट में कहा, ''विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष, बिहार प्रांत के माननीय अध्यक्ष, श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र के न्यासी, दो बार के सांसद व श्री रामलला के मंदिर की प्रथम ईंट रखने वाले श्री कामेश्वर चौपाल जी का निधन बेहद दुखद और स्तब्ध करने वाला है।''

फरीदाबाद: केंद्रीय मंत्री ने 38वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया

फरीदाबाद/भाषा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को यहां 38वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया।

शेखावत ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि दो बड़े ऐतिहासिक आयोजनों के माध्यम से भारत, विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां, भारत को सामाजिक समरसता और एकता के सूत्र में बांधने वाले महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वहीं, दूसरी ओर भारत की सांझी कलात्मक विरासत का प्रदर्शन करने वाले सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ है।

शेखावत ने कहा कि सूरजकुंड का यह मेला केवल कला को दिखाने का अवसर नहीं बल्कि शिल्पकारों और दस्तकारों की पुरातन परंपरा को दर्शाने का महान मंच है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' का जो स्वपन हम देख रहे हैं, यह मेला उस संदेश को चरितार्थ करने का काम कर रहा है।

वैज्ञानिक आधार पर युवाओं से जनसंख्या असंतुलन दूर करने का आह्वान: विहिप

महाकुंभ नगर/प्रयागराज/भाषा। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने जनसंख्या असंतुलन पर एम्स और अन्य संस्थानों के अध्ययनों का हवाला देते हुए शुक्रवार को युवाओं से दो या तीन बच्चे पैदा करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। विहिप के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने महाकुंभ नगर में विहिप शिविर में शुक्रवार से शुरू हुई तीन दिवसीय केंद्रीय प्रन्यासी (शासी) मंडल की बैठक के बाद कहा कि एम्स और अन्य संस्थानों ने अध्ययन में पाया है कि परिवार में अगर दो या तीन बच्चे होते हैं तो तभी बच्चों के विकास की अच्छी संभावना होती है और अकेला बच्चा विकास नहीं कर पाता। उन्होंने कहा, इस अध्ययन के आधार पर हमने युवाओं से दो या तीन बच्चे पैदा करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है।

पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यक लोग भाजपा को 2027 में सत्ता से बाहर करेंगे: अखिलेश

लखनऊ/भाषा। समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर दलितों और आदिवासियों को निशाना बनाने का शुक्रवार को आरोप लगाते हुए कहा कि पीडीए समुदाय (पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक) 2027 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता से बाहर कर देगा।

अखिलेश ने नोएडा में आरोप लगाया कि भाजपा मतदाताओं को दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान द्वारा दिए अधिकारों को छीन रही है। उन्होंने कहा, ''भाजपा सीओ (मंडल अधिकारी) और एसओ (थाना प्रभारी) जैसे पदों पर पीडीए (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) लोगों की नियुक्ति रोक रही है। पीडीए 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए एकजुट होगा।'' अखिलेश ने भाजपा पर चुनावों में हेराफेरी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि वहां मृतकों के नाम पर वोट डाले गए और फर्जी मतदान हुआ। उन्होंने निर्वाचन आयोग से जांच की मांग की और उस पर शिकायतों पर कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

'एचपीवी टीके को सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने पर हो रहा है मंथन'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम वाले एचपीवी (ह्यूनम पोपिलोमा वायरस) टीके को सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने को लेकर मंथन कर रही है।

लोकसभा में प्रश्नकाल में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की शांभवी चौधरी के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए अनुप्रिया पटेल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की सर्वाइकल(गर्भाशय) कैंसर की स्क्रीनिंग की जा रही है। उन्होंने कहा, ''सरकार एचपीवी टीके को सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने को लेकर चिंतन-मंथन कर रही है। यह अभी प्रक्रिया में है। जैसे ही कुछ तय होगा, हम सदन को सूचित करेंगे।''

अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा कि देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाए गए अभियानों से मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) और नवजात मृत्यु दर (आईएमआर) में दुनिया की तुलना में कमी आई है। उन्होंने कहा कि 1990 से 2020 तक एमएमआर की वैश्विक दर 42 प्रतिशत तक गिरी, वहीं भारत की दर 83 प्रतिशत कम हुई। इसी तरह दुनिया में आईएमआर में 55 प्रतिशत गिरावट आई है, लेकिन भारत में यह 69 प्रतिशत कम हुई।

पटेल ने कहा कि दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में सरकार के चलित दल जाते हैं और गर्भवती महिलाओं का पता लगाकर उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं।

श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। विपक्षी दलों के सांसदों ने श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में शुक्रवार को संसद के परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार से इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने की मांग की।

तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक), कांग्रेस और वाम दलों के सांसदों ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के डेरेक ओ ब्रायन एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के सुदामा प्रसाद समेत विपक्षी दलों के कई अन्य सांसद भी शामिल हुए।

प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने हाथों में तख्तियां पकड़ रखी थीं, जिसमें लिखा था, 'तमिल मछुआरों के लिए न्याय', 'हमारे मछुआरों को वापस लाओ', 'अब और गिरफ्तारी नहीं' तथा 'तमिलनाडु के मछुआरे भारतीय हैं।' द्रमुक सांसद तिरुचि शिवा ने कहा कि तमिल मछुआरों की गिरफ्तारी का मामला राष्ट्रीय मुद्दा है, क्योंकि वे भारतीय हैं और श्रीलंका में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। शिवा ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''कई अन्य दल भी प्रदर्शन में शामिल हुए। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे राज्य तक सीमित नहीं रखना चाहिए। वे तमिल मछुआरे हैं, वे भारतीय हैं।'' राज्यसभा के सदस्य ने कहा, ''मछुआरों को वर्षों से प्रताड़ित, परेशान और मारा जा रहा है और सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इससे पहले वे (श्रीलंकाई अधिकारी) उन पर हमला करते थे और उनका जाल छीन लेते थे, लेकिन अब तो उन्होंने गरीब मछुआरों पर गोली चलाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।''

महाकुंभ भगदड़ में मारे गये लोगों की संख्या छिपा रही सरकार : कांग्रेस

लखनऊ/भाषा। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर पिछले महीने प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ में जान गंवाने वाले और लापता हुए लोगों के सही आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को इसे 'संवेदनहीनता की पराकाष्ठा' करार दिया। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी मुख्यालय पर संवाददाताओं से कहा, पिछले महीने अव्यवस्था के कारण महाकुंभ में मची भगदड़ के कारण सैंकड़ों लोगों की मौत हो गई। हजारों लोग घायल हो गये और हजारों लोग लापता हो गये। उत्तर प्रदेश सरकार इतनी संवेदनहीन है कि अब तक लापता लोगों और मृतकों की कोई सही सूची जारी नहीं कर पाई।'' उन्होंने कहा, परिजन अपनों को तलाशते हुए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन योगी सरकार है कि सिर्फ अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए सही आंकड़ों को छिपा रही है। ऐसे कई मृतकों को धार्मिक नियमानुसार अंतिम क्रियाकर्म भी नसीब नहीं हुआ। कुछ लाशों को गंगा में बहा दिया गया, कुछ लाशों को बुलडोजर से उठाया गया, कुछ को विद्युत शवदाह गृह में गुमनाम तरीके से जला दिया गया और कुछ लाशें अभी भी कूड़ों के ढेर में पड़ी हुई हैं। संवेदनहीनता की यही पराकाष्ठा है शायद।

मणिपुर की एन.बीरेन सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस

इंफाल/भाषा। मणिपुर की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष के. मेघचंद्र ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी राज्य विधानसभा में एन. बीरेन सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। मेघचंद्र ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''ब्रह्मास्त्र मिसाइल निश्चित रूप से डबल इंजन में से एक को मार गिराएगी। कांग्रेस पार्टी जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है।'' हालांकि, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेघचंद्र ने पोस्ट पर कोई और जानकारी साझा नहीं की। साठ सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में कांग्रेस के पांच विधायक हैं। एक अन्य विपक्षी पार्टी एनपीपी के सात विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 32 विधायक हैं और उसे नगा पीपुल्स फ्रंट के पांच और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के छह विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। साठ सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में तीन निर्दलीय विधायक और कुकी पीपुल्स अलायंस के दो विधायक भी हैं।

त्रिपुरा में भाजपा नीत गठबंधन में सभी सहयोगी एकजुट: माणिक साहा

अगरतला/भाषा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शुक्रवार को दावा किया कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत गठबंधन सरकार के सभी सहयोगी एकजुट हैं। मुख्यमंत्री साहा का यह बयान टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) प्रमुख प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा के बुधवार को सोशल मीडिया पर जारी उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वादे पूरे नहीं किए गए, तो टीएमपी सत्ता से बाहर रह सकती है। टिपरा मोथा पार्टी त्रिपुरा में भाजपा की सहयोगी है। पश्चिमी त्रिपुरा जिले के नरसिंहगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए साहा ने कहा, ''ऐसा नहीं है...मैंने उनसे (प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा) बात की। हम एकजुट हैं। आज टीएमपी के सभी विधायक बैठक करने के लिए मेरे आवास पर आ रहे हैं। विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। राज्य में गठबंधन सरकार अच्छे से चल रही है। हम सभी एकजुट हैं।'' क्षेत्रीय पार्टी टीएमपी ने पिछला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था और 13 विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी।

वंदे भारत के यात्री टिकट बुकिंग के दौरान विकल्प नहीं चुनने पर भी ट्रेन में खरीद सकेंगे खाना : रेलवे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को कहा कि वंदे भारत ट्रेन के यात्री टिकट बुकिंग के दौरान यदि भोजन का कोई विकल्प नहीं चुनते हैं, तो वे रेलगाड़ी में भी इसे खरीद सकते हैं।

रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम(आईआरसीटीसी) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को जारी एक परिपत्र में कहा, ''वंदे भारत रेलगाड़ियों में 'करेंट बुकिंग' (चार्ट बनने के बाद और ट्रेन रवाना होने से पहले होने वाली) और (भोजन का) विकल्प नहीं चुनने वाले यात्रियों को विकल्प और पर्याप्त खानपान सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इन ट्रेनों में भोज्य पदार्थों की बिक्री और सेवा आईआरसीटीसी द्वारा फिर से बहाल की जा सकती है।''

परिपत्र में कहा गया है, ''करेंट बुकिंग और (भोजन का) विकल्प न चुनने वाले यात्रियों के लिए पका हुआ भोजन (यदि उपलब्ध हो) का विकल्प बहाल किया जा सकता है, जो 'रेडी टू इट' भोजन के विकल्प के अतिरिक्त होगा।'' रेलवे अधिकारियों ने कहा कि काफी संख्या में यात्री अक्सर शिकायत करते थे कि आईआरसीटीसी कर्मचारी उन्हें भोजन मुहैया नहीं कराते हैं, भले ही वे भुगतान करना चाहते हों। इसका कारण, यह बताया जाता था कि टिकट बुकिंग के दौरान उन्होंने यह विकल्प नहीं चुना था। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, ''अक्सर ऐसा होता है कि आप बुकिंग के समय 'प्रीपेड' भोजन का विकल्प नहीं चुनते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आप भोजन खरीदना चाहते हैं। इन मामलों में, आईआरसीटीसी कर्मचारी ऐसे यात्रियों के भुगतान करने के बाद भी इसे देने से मना कर देता है।'' उन्होंने कहा, ''अब नीतिगत तौर पर हमने तय किया है कि जिन यात्रियों ने 'प्रीपेड' भोजन का विकल्प नहीं चुना है, वे भी ट्रेन में गुणवत्तापूर्ण भोजन खरीद सकते हैं।''

लालू के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन मामला : अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान का आदेश टाला

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से जुड़े नौकरी के बदले जमीन 'घोटाले' में सीबीआई के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का आदेश शुक्रवार को 17 फरवरी तक के लिए टाल दिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अंतिम रिपोर्ट पर संघीय एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगते हुए मामले को स्थगित कर दिया।

तीस जनवरी को सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि उसने लोक सेवक आर के महाजन सहित सभी आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली है।

अधिकारियों ने बताया कि यह मामला रेलवे में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है। यह नियुक्तियां 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान की गई थीं।

आरोप है कि इन नियुक्तियों के बदले में राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन के टुकड़े उपहार में दिए गए।

केसीए ने श्रीसंत की आलोचना करते हुए कहा, वह मैच फिक्सिंग के आरोपों से बरी नहीं हुए हैं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुवनंतपुरम/भाषा। भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन के समर्थन में एस श्रीसंत की टिप्पणी से कथित तौर पर नाराज केरल क्रिकेट संघ (केसीए) ने इस पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज पर राज्य की क्रिकेट संचालन संस्था के खिलाफ गलत और अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया है।

केसीए ने हाल ही में एक मलयालम टीवी चैनल पर पैनल चर्चा के दौरान राज्य क्रिकेट निकाय और सैमसन से जुड़े मामले टिप्पणी की थी। जिसके बाद भारतीय टीम के साथ दो बार विश्व कप जीतने वाले श्रीसंत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। केसीए ने जारी बयान में कहा कि श्रीसंत को जारी कारण बताओ नोटिस का सैमसन मामले से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें यह नोटिस इस संघ के खिलाफ भ्रामक और अपमानजनक टिप्पणियों के लिए भेजा गया है। श्रीसंत ने टीवी चर्चा के दौरान कथित तौर पर सैमसन को अपना समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने सैमसन को राज्य की टीम में नहीं चुने जाने को लेकर केसीए को कटघरे में खड़ा करते हुए उनकी और केरल के अन्य खिलाड़ियों की रक्षा करने की कसम खाई।

श्रीसंत ने यह टिप्पणी उस समय की जब राज्य क्रिकेट बोर्ड भारतीय टी20 टीम के विकेटकीपर को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए केरल टीम से बाहर करने पर आलोचना का सामना कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे भारत की चैंपियंस ट्रॉफी टीम के लिए चुने जाने की उनकी संभावना प्रभावित हुई है। केसीए ने यह कहा कि पूर्व तेज गेंदबाज को अभी तक मैच फिक्सिंग मामले से बरी नहीं किया गया है।

डब्ल्यूपीएल ने मुझे पारी को संवारना सिखाया: शेफाली

पुणे/भाषा। दिल्ली कैपिटल्स की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने शुक्रवार को कहा कि महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) से उन्हें अपनी पारी संवारने का तरीका सीखने में मदद मिली और यह लीग खिलाड़ियों को अपने खेल को निखारने का अवसर प्रदान करती है। वर्मा दिल्ली कैपिटल्स की महत्वपूर्ण सदस्य है। उन्होंने पिछले दो डब्ल्यूपीएल में टीम को फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। वर्मा ने एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा, ''डब्ल्यूपीएल में खिलाड़ियों को अच्छी संख्या में मैच खेलने को मिलते हैं। आपको इस लीग में अपने खेल में यहां-वहां छोटे-छोटे बदलाव करने के कुछ बहुत अच्छे मौके मिलते हैं।'' उन्होंने कहा, ''व्यक्तिगत रूप से, मैंने डब्ल्यूपीएल का हिस्सा रहते हुए सीखा है कि अपनी पारी कैसे संवारनी है।'' वर्मा ने कहा कि डब्ल्यूपीएल में विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेलने से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला।

राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजी: लवलीना ने जीता स्वर्ण, शिव थापा को रजत से करना पड़ा संतोष

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

देहरादून/भाषा। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में शुक्रवार को यहां महिलाओं की 75 किग्रा स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता जबकि छह बार के एशियाई चैंपियन शिव थापा ने पुरुषों के 63.5 किग्रा वर्ग में रजत पदक हासिल किया।

पेरिस ओलंपिक के बाद अपना पहला टूर्नामेंट खेल रही असम की लवलीना ने तीनों दौर में चंडीगढ़ की युवा प्रतिद्वंद्वी प्रांशु राठौड़ पर एकतरफा 5-0 की जीत दर्ज की। थापा को पुरुषों के लाइट वेल्टरवेट (63.5 किग्रा) वर्ग के फाइनल में निराशा का सामना करना पड़ा। उन्हें सेना खेल संवर्धन बोर्ड के मुक्केबाज वंशज से करीबी मुकाबले में 4-3 से हराया। राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता सेना की जैस्मिन लम्बोरिया ने महिलाओं की 60 किग्रा स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप की कांस्य विजेता हरियाणा की मनीषा मौन पर 5-0 से जीत के साथ अपना दबदबा कायम किया। सेना के लिए एक और स्वर्ण पदक साक्षी ने जीता। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की विनाक्षी को 5-0 से हराया। दिन के अन्य मुकाबलों में सेना के मंडेंगबाम सिंह ने पुरुषों के फ्लाईवेट (51 किग्रा) वर्ग में चंडीगढ़ के अंशुल पूनिया को 4-1 खंडित फैसले से हराया। महिलाओं के बैंटमवेट वर्ग में मध्य प्रदेश की दिव्या पंवार ने उत्तर प्रदेश की सोनिया लाठेर को 4-1 से शिकस्त दी।

सुविचार

जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते है और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

अब भारत करे कार्रवाई

अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के तौर-तरीकों की आलोचना होने के बावजूद सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देशवासियों को दिखाना चाहते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान जो वादे किए थे, उन्हें मजबूती से निभा रहे हैं। अमेरिका के विभिन्न शहरों से अवैध प्रवासियों की धर-पकड़ के विरोध में स्वर तो उठे, लेकिन अब इस तर्क को भी समर्थन मिलने लगा है कि 'जो लोग चोरी-छिपे किसी देश में दाखिल हो जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए?' अभी अमेरिका ऐसे और लोगों को निकालेगा। इससे यह धारणा दृढ़ होगी कि अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए अवैध प्रवासियों को निकालना न्यायोचित है। अब इसी तर्क को आधार बनाकर भारत को भी अपनी जमीन पर रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं और तमाम घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर लेनी चाहिए। भारत इनका बोझ क्यों उठाए? भारत सरकार की जिम्मेदारी अपने नागरिकों का कल्याण करने की है। हमारे संसाधनों से अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य घुसपैठिए मौज क्यों उड़ाएं? भारतीय करदाताओं का एक-एक पैसा भारत के नागरिकों की सुख-समृद्धि के काम आना चाहिए। अब तो 'महाशक्ति' अमेरिका खुलकर स्वीकार कर चुका है कि उसके यहां महंगाई, बेरोजगारी और अपराधों में वृद्धि के पीछे अवैध प्रवासियों का बड़ा किरदार है। ये समस्याएं हमारे देश में भी हैं। यहां अवैध प्रवासी हमारे संसाधनों का लुत्फ उठा रहे हैं। वे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को संकुचित कर रहे हैं। उनमें से बहुत लोग अपराधों में लिप्त हैं। हाल में अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के आरोप में एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया था।

भारत में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यह बहुत अनुकूल समय है। प्राय: ऐसी कार्रवाइयों पर अमेरिकी सरकार बहुत सवाल उठाती है। उसके अधिकारी प्रेसवार्ताओं में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाते हुए यह जरूर कहते हैं कि 'हम स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं।' उसके कथित थिंक टैंक तो सालभर ही ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित करते रहते हैं, जिनमें 'असहिष्णुता' पर बहुत चिंता जताई जाती है। अब उनके पास भारत को ऐसी नसीहत देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ट्रंप के आदेश पर अवैध प्रवासियों को जंजीरों से जकड़कर सैन्य विमानों से रवाना किया जा रहा है। सोचिए, अगर भारत सरकार इससे आधी तादाद में अवैध प्रवासियों को यात्री विमान / वाहन में बहुत गरिमापूर्ण ढंग से भेजने की कोशिश करती तो अब तक कई संगठन इस कार्रवाई के विरोध में धरने पर बैठ जाते। कुछ बुद्धिजीवी तो अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए पूरी प्रक्रिया को अवरुद्ध करने की कोशिश करते। वे इन तर्कों के साथ इधर ही घुसपैठियों के टिके रहने का आधार तैयार करते- 'अब ये कहां जाएंगे ... हम तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं ... यहां इतने सारे लोग रहते हैं, ये भी रहेंगे तो क्या हो जाएगा ... क्या इन्हें निकालने से महंगाई कम हो जाएगी ... कभी तो हम एक ही थे ... ये सब लोग थोड़े ही अपराध करते हैं ... अगर इन्हें निकालेंगे तो अमेरिका क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी ...!' अवैध प्रवासियों की हिमायत में खड़े होने वाले संगठन अमेरिका में भी हैं, लेकिन राष्ट्रपति की सख्ती के आगे वे विवश हैं। ट्रंप को अमेरिकी नागरिकों से समर्थन मिल रहा है। वे स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी प्राथमिकता सूची में 'अमेरिका' और 'उसके लोगों की भलाई' हैं। उनकी कार्यशैली को पसंद या नापसंद किया जा सकता है, लेकिन इस बात से हर विवेकशील व्यक्ति सहमत होगा कि अपने नागरिकों को वंचित रखकर विदेश से अवैध ढंग से आए लोगों का पालन-पोषण करना उस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। भारत भी अपनी जमीन पर ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त न करे। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।

ट्वीटर टॉक

अंजू कुमारी ने पुलिस अधिकारी बनकर यह साबित किया है कि दृढ़ निश्चय और सही समर्थन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। राजस्थान सरकार की महिलाओं और युवाओं को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों ने उनकी राह को आसान बनाया है।

-भजनलाल शर्मा

हमारी सरकार के समय मैंने सदन के पटल पर कहा था कि किसी भी मंत्री, सांसद और विधायक का टेलिफोन सर्विलांस पर नहीं लिया गया और न ही लिया जाएगा। परन्तु भाजपा सरकार पर अपने ही कैबिनेट मंत्री द्वारा फोन टैपिंग के आरोप लगाना भाजपा की सच्चाई उजागर करता है।

-अशोक गहलोत

सेवा, समर्पण और त्याग की प्रतिमूर्ति रमाबाई अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें कोटिश: नमन। भारत रत्न बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर के संघर्षमयी सफर में उनका धैर्य और सहयोग अतुलनीय था। समाज के उत्थान में उनका अप्रत्यक्ष योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

-मदन दिलावर

प्रेरक प्रसंग

सोने की अशरफी और सेवा

एक बार एक सेठ अपने बच्चे को दिखाने के लिए एक नामी वैद्य के पास पहुंचा। बच्चे को देखने के बाद वैद्य ने औषधि की पहली खुराक वहीं पर पीने को दी। कुछ ही मिनटों में लाभ दिखाई देने लगा। सेठ ने वैद्य से पूछा, 'क्या फीस देनी होगी?' वैद्य ने कहा, 'आप सोने की एक अशर्फी दे दीजिए।' यह बात पास बैठा दूसरा मरीज भी सुन रहा था। उसने सोचा, 'इतनी कीमती अशर्फी मैं कैसे दे पाऊं?' और चुपचाप उठकर जाने लगा। वैद्य ने उसे रुकते हुए कहा, 'बेफिक्र रहिए, आपका इलाज तो मुफ्त में होगा। जब आप ठीक हो जाएं, तो आश्रम आकर दूसरों की सेवा कर देना।' यह सुनकर सेठ क्रोधित हो गया और बोला, 'वैद्यजी, आप तो बहुत लालची इंसान हैं! मेरा पैसा देखकर आपको लालच आ गया और मुझसे अशर्फी मांग बैठे, जबकि इसका इलाज आपने मुफ्त में कर दिया!' वैद्य मुस्कुराते हुए बोले, 'नहीं सेठजी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल, मेरे आश्रम को चलाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है धन और सेवा। जिस व्यक्ति के पास जो चीज होती है, मैं उससे वही मांगता हूं। आपके पास धन है, इसलिए मैंने आपसे धन लिया, और इस व्यक्ति के पास धन नहीं है, इसलिए ठीक होकर यह मेरे आश्रम में अपनी सेवा प्रदान करेगा।'

सामयिक

अवैध प्रवासन को तत्परता से हल करे भारत

डॉ. सत्यवान सौरभ

निर्वासित लोगों के लिए समान उपचार की गारंटी देने के लिए, भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए अनुकूल वीज़ा नीतियों पर बातचीत करें और कार्यबल गतिशीलता समाधानों पर यू.एस.एस. के साथ सहयोग करें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैन्य विमानों का उपयोग करके अनिर्दिष्ट भारतीय प्रवासियों को निर्वासित करते हुए अपने आव्रजन अभियान को आगे बढ़ाया है। इस क़दम से हजारों भारतीय नागरिक प्रभावित हैं, क्योंकि अमेरिका में अनुमानित 7, 25, 000 अनिर्दिष्ट भारतीय हैं। हालांकि, भारत ने पेशेवरों और छात्रों के लिए वैध प्रवास मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए अवैध अप्रवासियों की नागरिकता की पुष्टि के बाद उन्हें वापस भेजने की प्रतिबद्धता जताई है।

अमेरिका द्वारा अवैध अप्रवासी होने के कारण दर्जनों भारतीयों को निर्वासित करना न तो आश्चर्यजनक है और न ही नया। अमेरिका ने संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले लोगों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और निर्वासित करने के लिए, आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन ने अपने कार्यों को तेज कर दिया है, जिसमें निर्वासन भी शामिल है। गुजरात, पंजाब और हरियाणा के भारतीय उन लोगों में से हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। नौकरी की कमी और आर्थिक कठिनाई के कारण, कनाडा और मैक्सिको के माध्यम से अवैध रूप से लोग अमेरिका प्रवेश करते है। भारतीय सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कानूनी प्रवास मार्ग हों। अमेरिकी आव्रजन नीतियों का भारतीय पेशेवरों और छात्रों पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है? यू.एस. प्रतिबंध भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं। इन अधिकृत रास्तों में छात्र और कुशल श्रमिक एच-1बी वीजा शामिल हैं। यू.एस. एस और भारत दोनों ही अनधिकृत आव्रजन को हतोत्साहित करने के लिए काम कर रहे हैं, 2024 में निर्वासित भारतीयों की संख्या 2021 में 292 से बढ़कर 2024 में 1, 529 हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में, लगभग 725, 000 अनिर्दिष्ट भारतीय हैं। ज्यादातर गुजरात और पंजाब से। पिछले साल नवंबर तक, 20, 407 अनिर्दिष्ट भारतीयों को या तो अमेरिकी हिरासत सुविधाओं में हिरासत में लिया गया था या उन्हें अंतिम निष्कासन आदेशों का सामना करना पड़ा था।

निर्वासन का संयुक्त राज्य अमेरिका पर भी प्रभाव पड़ेगा? निर्माण और आतिथ्य जैसे उद्योग जो अप्रवासी श्रम पर निर्भर हैं, उन्हें श्रमिकों की कमी का अनुभव हो सकता है। उदाहरण के लिए, भारतीय मज़दूर यू.एस. आईटी और सेवा क्षेत्रों में पर्याप्त योगदान देते हैं। बड़े पैमाने पर निर्वासन यू.एस. पर दबाव डाल सकता है। हजारों भारतीयों का निर्वासन एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, विपक्षी दल सरकार पर घर पर पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान नहीं करने का आरोप लगा सकते हैं। इसका भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर निसंदेह प्रभाव पड़ सकता है? बड़े पैमाने पर निर्वासन भारत-अमेरिका सम्बंधों पर दबाव डाल

सकता है, खासकर अगर निर्वासितों को गंभीर व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जो राजनयिक कार्यवाही को बढ़ावा देता है। सैन्य विमानों के उपयोग और क्रूर व्यवहार के आरोपों से अमेरिका विरोधी भावना भड़क सकती है, जैसे कि जंजीरों में जकड़ना। गुजरात, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में राजनीतिक अशांति हो सकती है, जहाँ बड़ी संख्या में निर्वासित हैं। स्थानीय सरकारों पर नौकरी देने और पुनः एकीकरण में सहायता करने का दबाव हो सकता है। अवैध रूप से प्रवास करने की कोशिश करने वालों के लिए, भारत सरकार मानव तस्करी संगठनों और अवैध आव्रजन के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए मजबूर हो सकती है। अनिर्दिष्ट प्रवासियों के व्यापक प्रत्यावर्तन का परिवार के वित्तीय समर्थन, प्रेषण और भारतीय प्रवासियों के बारे में आम जनता की राय पर प्रभाव पड़ सकता है।

गिरफ़्तारियों में वृद्धि के कारण कई भारतीय अनिर्दिष्ट कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्रों से दूर रहने लगे हैं। कम वेतन वाले उद्योगों में, घरों और रोज़गार के स्थानों पर नज़रबंदी ने अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला है। एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि प्रायोजन की ज़रूरतें बदल सकती हैं। कई भारतीय छात्र वीज़ा नवीनीकरण के बारे में सख्त नियमों से डरते हैं। वैध प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, भारत स्थिति पर सावधानीपूर्वक नज़र रख रहा है। अमेरिकी विधायकों के साथ राजनयिक बातचीत का लक्ष्य रोज़गार-आधारित आव्रजन नीतियों को बनाए रखना है। ट्रम्प प्रशासन ने अनिर्दिष्ट प्रवासियों पर अपनी कार्यवाही के तहत निर्वासित लोगों की संख्या में वृद्धि की है। माना जाता है कि 7, 25, 000 भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं और 20, 407 अनिर्दिष्ट भारतीयों को निकालने का लक्ष्य बनाया गया है। भारत अनिर्दिष्ट अप्रवासियों को वापस भेजने के लिए सहमत है, बशर्ते उनकी नागरिकता की पुष्टि हो। ट्रम्प ने उन देशों को टैरिफ़ लगाकर अनुपालन करने के लिए मजबूर किया है जो निर्वासित प्रवासियों को लेने से इनकार करते हैं। हालांकि कुशल श्रमिकों के प्रवास के सम्बंध में नीतिगत परिवर्तन अपेक्षित हैं, लेकिन एच-1बी वीजा धारकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

ऐसे में भारत विशिष्ट आर्थिक सुधार लागू करें, प्रवास की उच्च दर वाले राज्यों (गुजरात, पंजाब और हरियाणा) में रोजगार बढ़ाएँ और अवैध प्रवास को बढ़ावा देने वाले अंतर्निहित मुद्दों जैसे कि बेरोज़गारी और कृषि कठिनाई से निपटें। कुशल प्रवास के लिए सुरक्षित और कानूनी मार्ग बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय समझौतों का उपयोग करते हुए अवैध आव्रजन के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाएँ। निर्वासित लोगों के लिए समान उपचार की गारंटी देने के लिए, भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए अनुकूल वीज़ा नीतियों पर बातचीत करें और कार्यबल गतिशीलता समाधानों पर यू.एस.एस. के साथ सहयोग करें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैन्य विमानों का उपयोग करके अनिर्दिष्ट भारतीय प्रवासियों को निर्वासित करते हुए अपने आव्रजन अभियान को आगे बढ़ाया है। इस क़दम से हजारों भारतीय नागरिक प्रभावित हैं, क्योंकि अमेरिका में अनुमानित 7, 25, 000 अनिर्दिष्ट भारतीय हैं। हालांकि, भारत ने पेशेवरों और छात्रों के लिए वैध प्रवास मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए अवैध अप्रवासियों की नागरिकता की पुष्टि के बाद उन्हें वापस भेजने की प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिका की अपनी अगली यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय व्यापार, आव्रजन और कूटनीतिक सहयोग के बारे में उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे।

नजरिया

पंजाब में फैलता ईसाई मिशनरियों का जाल !

अशोक भाटिया

मो.: 9221232130

चमत्कार और प्रलोभन के दम पर पंजाब में ईसाइयत का प्रसार लगातार बढ़ता जा रहा है। पटियाला से लेकर पठानकोट तक ईसाई मिशनरियों का साम्राज्य फैल रहा है। केवल दो साल के भीतर ही साढ़े 3 लाख लोगों का धर्मांतरण हुआ है। आज पंजाब बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। भारत में कुल तीन राज्य ऐसे हैं, जो ईसाई बहुल हैं। इनमें नगालैंड में 87।9 पर्सेंट, मिजोरम में 87।2 पर्सेंट और मेघालय में 74।6 पर्सेंट आबादी ईसाई धर्म के लोगों की है। उत्तर पूर्व के बाद गोवा में सबसे ज्यादा 25।1 पर्सेंट, केरल में 18।4 पर्सेंट, तमिलनाडु में 6।1 पर्सेंट और झारखंड में 4।3 पर्सेंट लोग ईसाई धर्म से हैं। ईसाई मिशनरी ईसाई धर्म से जुड़ी उन संस्थाओं और लोगों को कहा जाता है, जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करती हैं। लेकिन सिख धर्म से जुड़े संगठनों का आरोप है कि ये मिशनरी पंजाब के सैकड़ों गांवों में धर्म परिवर्तन के लिए कई तरह के अभियान चला रही हैं। और इसमें अलग-अलग पादरी गांवों में घूम घूमकर लोगों को ये बताते हैं कि कैसे उनके प्रार्थना करने से लोगों की बीमारियां ठीक हो सकती हैं और कैसे ईसाई धर्म लोगों का कल्याण कर सकता है। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स और निजी संस्थाओं द्वारा कराए गए सर्वे बताते हैं कि पंजाब में धर्म परिवर्तन के कारण ईसाई धर्म की आबादी में कई गुना वृद्धि हुई है। बताया जाता है कि ईसाई मिशनरियां भ्रम और अंधविश्वास फैलाकर न केवल भारतीय समाज को तोड़ रही हैं, बल्कि कन्वर्जन कर समाज को लगातार कमजोर करने का प्रयास भी कर रही हैं। पिछले लगभग दो दशकों में पेंटेकोस्टल आंदोलन से प्रेरित कथित करिश्माई ईसाइयत की ऐसी लहर चली कि अब पंजाब का कोई भी जिला इससे अछूता नहीं रह गया है। सभी 23 जिलों में ईसाइयों ने अपनी पैठ बना ली है। विशेषकर, समूचे माझा, दोआबा क्षेत्र, पंजाब के मालवा क्षेत्र में फिरोजपुर और फाजिल्का के सीमावर्ती क्षेत्रों में ईसाई बहुत बड़ी संख्या में हो गए हैं। राज्य में बड़े पैमाने पर चल रहे कन्वर्जन को लेकर सिख और हिंदू समाज आक्रोशित है, जिसकी परिणति अक्सर होने वाले संघर्षों के रूप में देखी जा सकती है।

वैसे पंजाब में कितने चर्च और पादरी हैं, इसका कोई ठोस आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लेकिन अनुमान है कि यहां पादरियों की संख्या लगभग 65,000 है। इनमें लगभग 5,000 पादरी तो ऐसे हैं, जिन्होंने हाल ही में ईसाइयत कबूल की है। इनमें से अधिकांश आज भी लोगों को बरगलाने के लिए हिंदू-सिख नाम और हिंदू सिख वेश बनाए रखे हुए हैं तथा सिख और हिंदू समाज के लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। पंजाब में ऐसा कोई गांव, नगर और शहर नहीं है, जहां चर्च न हों। बल्कि घरों में ही चर्च खुल गए हैं, जहां लालच देकर सिखों और हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है। कन्वर्जन की फांस में नौ वंचित समुदायों की बड़ी संख्या है। इनमें रविदासी (मजहबी सिख), वाल्मीकि, सांसी, बावरिया, बाजीगर, राय सिख, बराड़, बंगला, गाधिले और नट शामिल हैं। इसके अलावा, कुछ ब्राह्मण परिवार भी इनके अनुयायी हैं। राज्य में उभरती क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। हालांकि सूबे में चर्च आफ नॉर्थ इंडिया है, जिसके अंतर्गत उत्तर भारत के अधिकांश प्रोटेस्टेंट चर्च आते हैं। दूसरी ओर जालंधर डायोसिस के अंतर्गत पंजाब के 23 में से 15 जिलों के अलावा हिमाचल प्रदेश के चार जिलों के रोमन कैथोलिक चर्च आते हैं। लेकिन ये मिनिस्ट्रीज इनमें से किसी के साथ संबद्ध नहीं हैं। स्वतंत्र रूप से काम कर रहे इन पादियों को एक छतरी के नीचे लाने के हरप्रीत देओल ने पेंटेकोस्टल चर्च प्रबंधक समिति बनाई, जिससे 1,000 से अधिक स्थानीय पादरी जुड़ चुके हैं।

कहा जा रहा है कि कि पिछले कुछ समय से तथाकथित ईसाई मिशनरी चमत्कारिक इलाज और कपटपूर्ण सिखों का जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पंजाब के सिखों और हिंदुओं को ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराने के लिए उन्हें गुमराह किया जा रहा है और यह सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। दरअसल भारत के कानून में धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण कोई भी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है।

वहां के लोगों का कहना है कि हम अपने धर्म में भी चमत्कारिक इलाज (पाखंडवाद) के खिलाफ हैं। बाइबल भी ऐसे लोगों की निंदा करती है, लेकिन यहाँ इस तरह के अंधविश्वासों का इस्तेमाल पंजाब के लोगों को लुभाने के लिए किया जा रहा है।ज्ञात हो कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और यहाँ के गरीब हिंदुओं और सिखों को धर्मांतरित करने के लिए 'विदेशी ताकतें' फंडिंग कर रही हैं। उन्होंने इसे चिंताजनक बताते हुए स्थानीय लोगों का कहना है कि अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके अनुसार धर्मांतरण करने वाले लोग आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं। यह कैसे हो रहा है, यह एक प्रश्न है।

गौरतलब है कि पंजाब जैसे आधुनिक व वैज्ञानिक सोच वाले राज्य में भी अगर धर्म परिवर्तन से जुड़ी खबरें आती रहती हैं तो यह वास्तव में बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि यह भारत का एक मात्र ऐसा राज्य है जहां के लोगों को सिख गुरुओं ने सबसे पहले धार्मिक पाखंडवाद को नकारने का पाठ पढ़ाया और कर्म (कार्य) की शक्ति में विश्वास रखने का उपदेश दिया। यहां के लोगों की उदात्त संस्कृति ने मानवीयता को मजहब की चारदीवारी के घेरे में कैद करने से इनकार किया जिसमें सिख गुरुओं का ही सबसे बड़ा योगदान रहा क्योंकि उन्होंने 'मानस की जात' को एक ही रूप मे पहचाना। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविन्द सिंह महाराज तक सभी दस गुरुओं ने अन्याय के समक्ष कभी भी सिर न झुकाने को मानव धर्म बताया और सत्य व हक की राह में बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए प्रेरित किया। दीन-हीन की सेवा को मानव कर्त्तव्य बताया और कर्म या मेहनत करने को ईमान बताया। सिख गुरुओं ने सबसे बड़ा उपदेश यह दिया कि किसी दैवीय चमत्कार पर भरोसा करने के बजाय मनुष्य अपनी मेहनत और लगन पर यकीन रख कर ही अपने जीवन में चमत्कार कर सकता है। इसका प्रमाण आज हम स्वयं केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में देख सकते हैं क्योंकि जिस प्रान्त या देश में भी पंजाबी हैं वे अपनी मेहनत व कार्यक्षमता के बूते पर ही आगे बढे हैं ।

ऐसे समाज में यदि किसी विशेष मजहब के प्रचारक यहां के सिख व हिन्दुओं को दैवीय चमत्कारों के जाल में फंसा कर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं तो इसका संज्ञान लिये बिना नहीं रहा जा सकता। पिछले कुछ वर्षों से पंजाब में ईसाई मिशनरी यहां के सिख व हिन्दू युवकों विशेष रूप से पिछड़े वर्ग के समाज में अपने धार्मिक दैवीय चमत्कारों के नाम पर इसाई बनाने का अभियान चलाये हुए हैं। यह अभियान पंजाब के सरहदी जिलों में विशेष तौर पर चलाया जा रहा है।

ये ईसाई मिशनरी धार्मिक पाखंड फैला कर इन लोगों को सम्मोहित करने का प्रयास करते हैं और फिर उनकी धार्मिक पहचान को अनावश्यक बता कर केश त्यागने को कहते हैं तथा ईसाई बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इस बारे में पिछले वर्ष भी सिख समुदाय के कई जत्थेदारों ने ध्यान खींचने की कोशिश की थी। परन्तु तत्कालीन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। परन्तु इस बार वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से सरकार से मांग की है कि धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए एक कानून लाया जाये जिससे राज्य में पाखंडवाद और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगाम लग सके। वैसे स्वयं में यह कम आश्चर्य का विषय नहीं है कि पंजाब जैसे राज्य के लोग भी अंधविश्वास का शिकार हो सकते हैं परन्तु भौतिक लालच और रातोंरात परिस्थितियों के बदलने के मोह में व्यक्ति ऐसे चक्करों में फंस भी सकता है, जिसका लाभ ईसाई मिशनरियां संभवतः उठा रही हैं। वरना कोई वजह नहीं थी कि वहां के जागरूक लोगों को स्वयं ही इस बुराई को खत्म करने की कमान संभालने की कार्रवाई करनी पड़ती।

यदि गौर से देखा जाये तो सिख गुरुओं ने ही हिन्दू धर्म में फैले पाखंडवाद को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था और मनुष्य को अपने ऊपर भरोसा करने का सन्देश दिया था। आज भी सिख संगतों में हमें ये उपदेश सुनने को मिलते हैं। जात- पांत के विरुद्ध भी सिख गुरुओं ने व्यापक अभियान चलाया और हर इंसान को एक समान समझने का व्यावहारिक गुर भी सिखाया। गुरुद्वारों में अनवरत लंगर चलना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसमें हर दीन व मजहब के आदमी की सेवा खुली रहती है। परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि पंजाब में जो पिछड़े या दलित वर्ग के लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित होते हैं उन्हें ईसाई बनने के बावजूद आरक्षण की सुविधाएं मिलती रहती हैं जबकि आरक्षण की सुविधा केवल हिन्दू व सिख धर्म के दलितों को ही मिल सकती है। वैसे देखा जाये तो अंधविश्वास बढ़ाने के खिलाफ भी देश में बाकायदा कानून है मगर इसका उपयोग करने से विभिन्न राज्य सरकारें इसलिए घबराती हैं कि इसमे वोट बैंक का मसला आकर फंस जाता है।

खुद को चमत्कारिक बताने वाले लोग हर मजहब में आसन जमा कर बैठे हैं। केवल सिख धर्म ही ऐसा है जिसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि इसके सन्त व धार्मिक उपदेशक गुरुओं के बताये मार्ग पर चलने के उपदेश देते हैं और उस 'गुरु ग्रन्थ साहब' को अपना प्रेरक मानते हैं जिसमें दलित व पिछड़े वर्ग के सन्तों की वाणियां भी संग्रहित हैं। इनमे अंधविश्वास व पोंगापंथी व पाखंडवाद पर करारा प्रहार होता है। अतः सवाल पाखंडवाद को समाप्त करने भी है जिसे फैला कर ईसाई मिशनरियां पंजाब का सामाजिक सौहार्द्र खराब करना चाहती है। दूसरा सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा का भी है क्योंकि इस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान से छूती हैं। भारत में धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव राष्ट्रीय नजरिये पर पड़ता है। धर्म परिवर्तित होते ही व्यक्ति की निष्ठाएं भारत की पुण्य भूमि से किसी दूसरी भूमि की तरफ घूमने लगती हैं। यह व्यावहारिक वास्तविकता है। ज्ञात हो कि भारतीय संविधान के (अनुच्छेद 25-28) अनुसार कोई व्यक्ति अपनी पसंद से कोई भी धर्म चुन सकता है, और उसका प्रचार-प्रसार कर सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति का धर्म जबरन या लालच देकर नहीं कराया जा सकता। भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए और 298 के अनुसार यह एक दंडनीय अपराध है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कानून बने हैं। अतः ज्ञानी जी की मांग पर धर्म परिवर्तन निषेध कानून पंजाब में लाया जाना चाहिए और विदेशी फंडिंग से धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों को सबक सिखाना चाहिए ।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।– दक्षिण भारत राष्ट्रमत

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन के प्रतिबंधों की आलोचना की

हेग/एपी

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने शुक्रवार को अपने सदस्य देशों से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ खड़े होने का आह्वान करते हुए कहा कि यह कदम उसके स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक कार्य को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय 'व्हाइट हाउस' ने प्रतिबंधों के संबंध में बृहस्पतिवार को कार्यकारी आदेश जारी किया। अमेरिका का कहना है कि उसे और उसके करीबी सहयोगी इजराइल को निशाना बनाने वाली अवैध और निराधार कार्रवाइयों के कारण उसने यह कदम उठाया है।

इस आदेश में पिछले साल गाजा में कथित युद्ध अपराधों के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट का संदर्भ दिया गया। हेग स्थित न्यायालय ने कहा कि वह इस कदम की ''निंदा'' करता है। न्यायालय ने एक बयान में कहा, ''न्यायालय अपने कर्मियों के साथ मजबूती से खड़ा है और दुनिया भर में अत्याचारों के लाखों निर्दोष पीड़ितों को न्याय और उम्मीद प्रदान करना जारी रखने का संकल्प लेता है।''

बयान में कहा गया, ''हम अपने 125 सदस्य देशों, नागरिक समाज और दुनिया के सभी देशों से न्याय और मौलिक मानवाधिकारों के लिए एकजुट होने का आह्वान करते हैं।''

आदेश में कहा गया है कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ठोस कदम उठाएगा। कार्रवाई में संपत्ति पर रोक और आईसीसी के अधिकारियों, कर्मचारियों और रिश्तेदारों को अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देना शामिल हो सकता है। कोषागार और विदेश विभाग यह निर्धारित करेंगे कि किन लोगों और संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। मानवाधिकार समूहों ने भी अमेरिका के इस निर्णय की आलोचना की है। 'ह्यूमन राइट्स वॉच' की अंतरराष्ट्रीय न्याय निदेशक लिज इवेनसन ने एक बयान में कहा, ''अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अधिकारियों के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध दुनिया भर में सामूहिक अत्याचारों के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए एक उपहार होगा। प्रतिबंध मानवाधिकार उल्लंघनकर्ताओं के लिए हैं, न कि उन लोगों के लिए जो अधिकारों का हनन करने वालों को जवाबदेह ठहराने का काम कर रहे हैं।'' इवेनसन ने कहा, ''ट्रंप का कार्यकारी आदेश रूस की कार्यप्रणाली के समान है, जिसने न्यायाधीशों और अभियोजक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के माध्यम से अदालत के काम में बाधा डालने की कोशिश की है।'' न्यायालय के अधिकारी महीनों से प्रतिबंधों से निपटने की तैयारी कर रहे थे। जनवरी में, न्यायालय ने कर्मचारियों को उनके तीन महीने के वेतन का अग्रिम भुगतान किया था। वहीं, प्रतिबंधों से बचने के प्रयास में ट्रंप के निर्वाचित होने के बाद से न्यायालय के कम से कम दो वरिष्ठ कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया।

पुलिस सेवा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में आयोजित दो दिवसीय भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) समागम 2025 के उद्घाटन के दौरान ।

शिरकत

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य शुक्रवार को मुंबई में एडवांटेज विदर्भ 2025 के दूसरे संस्करण में शामिल हुए।

बांग्लादेश में अवामी लीग के नेताओं के घरों पर हमले, तोड़फोड़ और आगजनी

ढाका/भाषा

बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं के घरों पर हमले करने के साथ आगजनी की और 24 से अधिक जिलों में देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के भित्ति चित्रों को नष्ट कर दिया गया। मीडिया में आईं खबरों से यह जानकारी मिली। यह अशांति बुधवार रात हसीना के ऑनलाइन संबोधन से शुरू हुई, जब प्रदर्शनकारियों ने शेख मुजीब के घर को निशाना बनाया।

शुक्रवार को ढाका के बनानी में अवामी लीग के नेता शेख सलीम के घर में आग लगा दी गई। सलीम के घर पर बृहस्पतिवार देर रात करीब डेढ़ बजे आग लगाई गई थी।

यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश (यूएनबी) ने अग्निशमन सेवा नियंत्रण कक्ष के अधिकारी के हवाले से बताया कि सुरक्षा कारणों से अग्निशमन सेवा के वाहन रात पौने तीन बजे तक घटनास्थल पर नहीं पहुंच सके। 'डेली स्टार' ने शुक्रवार को बताया कि शेख मुजीब के धानमंडी-32 में स्थित आवास को आग लगाने और ढहा दिए जाने के एक दिन बाद प्रदर्शनकारियों ने नोआखली के कम्पनीगंज में अवामी लीग (एएल) के महासचिव और पूर्व सड़क, परिवहन एवं पुल मंत्री ओबैदुल कादर के घर पर हमला कर तोड़फोड़ की और आग लगा दी।

दोपहर करीब एक बजे बोरा राजापुर मोहल्ले में स्थित घर पर हुए हमले के दौरान, कादर के छोटे भाई तथा कम्पनीगंज के अवामी लीग के अध्यक्ष अब्दुल कादर मिर्जा और बसुरहाट नगरपालिका के पूर्व महापौर शहादत मिर्जा के दो मंजिला भवन तथा टिन की छत वाले कमरों में भी तोड़फोड़ की गई।

घर के सामने खड़ी एक कार भी आग के हवाले कर दी गई। उस समय घर पर कोई नहीं था।

यूएनबी की खबर के अनुसार, राजशाही में प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बाघा उपजिला के चकसिंगा मोहल्ला में पूर्व विदेश राज्य मंत्री शहरयार आलम के तीन मंजिला मकान में आग लगा दी।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाघा और चारघाट उपजिलों से 100 से अधिक लोग मोटरसाइकिलों पर वहां पहुंचे और दोपहर के समय घर में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने कल पबना के शालगरिया गांव में अवामी लीग के नेता अबू सईद के घर पर भी हमला किया और उसे आग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने बृहस्पतिवार को गेट तोड़कर घर में तोड़फोड़ की और फिर शाम को उसमें आग लगा दी। बृहस्पतिवार को कमिला में प्रदर्शनकारियों ने शहर में शेख मुजीब के दो भित्तिचित्रों को नष्ट कर दिया।

वे शाम चार बजे के आसपास कमिला अदालत परिसर में बुलडोजर लेकर गए और एक अदालत की इमारत के सामने एक भित्तिचित्र को नष्ट कर दिया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, 'स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन' की कमिला शहर इकाई के सचिव रशीदुल हक ने कहा, ''हम फासीवाद की सभी निशानियों को मिटा देंगे।''

बाद में, कमिला सिटी पार्क में शेख मुजीब के एक और भित्तिचित्र वाले आधार को बुलडोजर से गिरा दिया गया। नारायणगंज में, बीएनपी समर्थक वकीलों ने नारायणगंज अदालत परिसर और शहर में उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों में शेख मुजीब के भित्तिचित्र वाले आधार और एक प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया।

मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने कहा कि देश भर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं का दृढ़ता से विरोध किया जाएगा।

अंतरिम सरकार ने एक बयान में कहा, अंतरिम सरकार इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि कुछ व्यक्ति और समूह देश भर में विभिन्न संस्थानों और प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ और आगजनी का प्रयास कर रहे हैं।

हथकड़ी लगाकर अवैध प्रवासियों को वापस भेजने पर भारत ने कहा, इससे बचा जा सकता था

नई दिल्ली/भाषा। भारत ने शुक्रवार को कहा कि उसने हथकड़ी लगाकर अवैध प्रवासियों को वापस भेजे जाने के मुद्दे पर अमेरिका के समक्ष चिंता व्यक्त की है। इसने यह भी कहा कि इस तरह के व्यवहार से बचा जा सकता था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की यह टिप्पणी अमेरिका द्वारा अवैध भारतीय प्रवासियों को सैन्य विमान में 40 घंटे की उड़ान के दौरान हथकड़ी लगाकर वापस भेजे जाने पर मचे बवाल के बीच आई है।

मिस्री ने प्रवासियों को भेजे जाने से संबंधित प्रश्नों पर कहा, ''हमने अपनी चिंताओं से अमेरिका को अवगत कराया है कि इस प्रकार के व्यवहार से बचा जा सकता है।'' उन्होंने कहा कि अमेरिका से भेजे जाने के लिए 487 भारतीय नागरिकों को चिह्नित कर लिया गया है और 298 लोगों का विवरण भारत के साथ साझा किया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी का सत्यापन किया जा रहा है।

विदेश सचिव ने कहा कि हथकड़ी लगाकर अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की अमेरिकी नीति 2012 से ही लागू है। विदेश सचिव से जब पूछा गया कि क्या भारत ने 2012 में हथकड़ी लगाकर अवैध प्रवासियों को वापस भेजने पर अपना विरोध दर्ज कराया था, तो उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि कोई विरोध जताया गया था। हमारे पास आपत्ति के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं है।'' मिस्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा बृहस्पतिवार को संसद में दिए गए बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा, ''विदेश मंत्री ने मानक संचालन प्रक्रिया से अवगत कराया जैसा कि अमेरिकी अधिकारियों ने आव्रजन और सीमा शुल्क नियमन पर सूचित किया था।'' उन्होंने कहा कि मंत्री ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया किया कि ऐसी प्रक्रिया 2012 से ही प्रचलन में है।

'गुम है किसी के प्यार में' गाना मेरे दिल के बहुत करीब : रेखा

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रेखा का कहना है कि गाना गुम है किसी के प्यार में उनके दिल के बहुत करीब है। स्टार प्लस के शो 'गुम है किसी के प्यार में' एक नए रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां इमोशनल ड्रामा, जबरदस्त ट्विस्ट और गहरी भावनाओं की झलक देखने को मिलेगी। हाल ही में रिलीज़ हुए प्रोमो ने दर्शकों में जबरदस्त उत्सुकता जगा दी है, और इस बार सबसे बड़ी खासियत हैं लीजेंडरी अभिनेत्री रेखा। रेखा की भावनाओं से भरी आवाज़ इस कहानी को और भी खास बना देती है, जो तेजस्विनी के जज़्बातों के उतार-चढ़ाव को बखूबी दर्शाती है। नील के साथ बेमेल शादी की उलझन और अपने पहले प्यार रुतुराज की वापसी के बीच फंसी

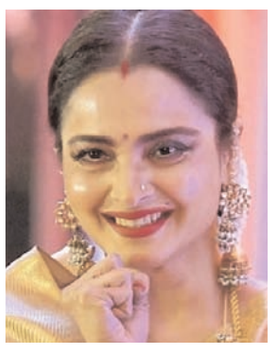

तेजस्विनी की कहानी दर्शकों को गहराई तक छू जाएगी। रेखा की आवाज़ इस सफर को और भी भावुक और यादगार बना रही है, जो शो को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। शो में नई कास्ट की एंट्री हुई है, जिसमें वैभवी हंकारे (तेजस्विनी), सनम जौहर (रुतुराज) और परम सिंह (नील) शामिल हैं। रेखा की बेमिसाल ग्रेस और उनकी भावनाओं से भरी आवाज़ ने प्रोमो को और भी खास बना दिया है, जिससे कहानी को एक अलग ही गहराई मिल रही है। रेखा ने कहा, गुम है किसी के प्यार में हमेशा से मेरे दिल के करीब रहा है।

जैसे-जैसे इसका नया सीजन सामने आ रहा है, मैं एक ऐसी कहानी का इंतज़ार कर रही हूं जो इंसानी जज़्बातों, प्यार, कर्तव्य, परिवार और जूनून जैसे पहलुओं को गहराई से टटोलती है। इसके टाइटल सॉन्ग 'गुम है किसी के प्यार में' का मेरे दिल में खास स्थान है, यह मुझे शांति देता है। इस शो के साथ मेरा यह जुड़ाव गर्मजोशी और सम्मान से भरा रहा है, और मैं आगे भी दर्शकों के लिए यादगार लम्हे बनाने को लेकर उत्साहित हूं।

मुलाकात

अठारहवीं लोकसभा के बजट सत्र के दौरान संसद भवन में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और अन्य सांसद शुक्रवार को मुलाकात करते हुए।

फिल्म 'हेरा फेरी-3' में हुई अभिनेत्री तब्बू की एंट्री

मुंबई/एजेन्सी

फिल्म 'हेरा फेरी-3' में अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी की तिकड़ी लोगों को मनोरंजन करने के लिए आ रही है। इस फिल्म 'हेरा फेरी-3' की आधिकारिक घोषणा कुछ महीने पहले की गई थी। फिल्म की शूटिंग इस समय चल रही है। इस फिल्म में अभिनेत्री तब्बू की एंट्री की अटकलें लग रही हैं। इस फिल्म के लिए तब्बू की चर्चा एक पोस्ट को लेकर हो रही।

तब्बू ने फिल्म 'हेरा फेरी' के पहले भाग में अनुराधा की भूमिका निभाई थी। उनकी यह भूमिका आज भी कई लोगों को याद है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तब्बू फिल्म 'हेरा फेरी-3' में नजर आएंगी। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिया, हेरा फेरी 3 मेरे बिना अधूरी है। तब्बू ने इस पोस्ट को प्रियदर्शन को टैग किया। अगर तब्बू 'हेरा फेरी-3' में नजर आती हैं तो यह और भी मजेदार होगा।

फिल्म 'हेरा फेरी-3' में एक बार फिर राजू, श्याम और बाबूभाई का किरदार निभा रहे क्रमश: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा अभी यह पता नहीं चल पाया है कि इन तीनों कलाकारों के साथ और कौन नजर आएगा। अगर तब्बू भी इन तीनों के साथ होंगी तो यह मजेदार होगा।

पहले 'हेरा फेरी-3' का निर्देशन फरहाद सामजी करने वाले थे, लेकिन अब कॉमेडी फिल्मों के निर्देशन में माहिर प्रियदर्शन 'हेरा-फेरी 3' के निर्देशन की कमान संभालेंगे।

'ऊप्स! अब क्या?' का ट्रेलर रिलीज किया

मुंबई/एजेन्सी

डिज्नी+ हॉटस्टार ने प्रेम मिस्त्री और देबात्मा मंडल निर्देशित और डाइस मीडिया निर्मित सीरीज ऊप्स अब क्या? का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ऊप्स अब क्या? एक युवा महिला के उतार-चढ़ाव भरे जीवन का अनुसरण करती है, जिसकी पूरी तरह से योजनाबद्ध दुनिया एक आकस्मिक कृत्रिम गर्भाधान के बाद हास्य पागलपन में बदल जाती है। यह सीरीज़ सिर्फ़ कॉमेडी का तड़का नहीं है, बल्कि तीन पीढ़ियों की महिलाओं की दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो परंपरा, आधुनिकता और प्यार के बीच सबसे अप्रत्याशित परिस्थितियों में आगे बढ़ती हैं। इस सीरीज में श्वेता बसु प्रसाद, आशिम गुलाटी, जावेद जाफ़री, सोनाली कुलकर्णी, अपारा मेहता, अभय महाजन और एमी ऐला की अहम भूमिका है।

ट्रेलर में तीन पीढ़ियों की महिलाओं के बीच होने वाले मज़ेदार और दिल को छू लेने वाले नाटक की झलक मिलती है, जिसमें वे प्यार, परंपरा और आधुनिकता के बीच तालमेल बिठाती हैं। साथ ही पागलपन का एक पहलू भी। श्वेता बसु प्रसाद ने कहा, जिस क्षण मैंने ऊप्स! अब क्या? की स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे पता था कि यह एक पागलपन भरा सफ़र

होने वाला है। मेरे किरदार की ज़िंदगी कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से व्यवस्थित से पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो जाती है, और यह सब बहुत ही हास्य और दिल से दिखाया गया है। यह प्यार, हसी और पागलपन के बीच खुद को खोजने की कहानी है। मुझे पता है कि दर्शकों को इसे देखने में और भी मज़ा आएगा।

जावेद जाफ़री ने कहा, मुझे ऊप्स! अब क्या? में जो बात पसंद आई, वह यह है कि यह जीवन की बेतुकी बातों से दूर नहीं है। ट्रेलर दिखाता है कि जीवन कितना अप्रत्याशित और मज़ेदार हो सकता है।यह एक ऐसी कहानी है जो परिवार, प्यार और रिश्तों के साथ-साथ हंसी के बारे में भी है। यह काफी धमाकेदार होने वाली है। सोनाली कुलकर्णी ने कहा, जब जीवन आपको अप्रत्याशित परिस्थितियों से रूबरू कराता है, तो कभी-कभी केवल हंसना ही एकमात्र काम होता है, और ऊप्स! अब क्या? बिल्कुल इसी बारे में है! अपनी बेटी की पागलपन भरी यात्रा का समर्थन करते हुए अपनी चुनौतियों से जूझने वाली आधुनिक माँ की भूमिका निभाना एक अविश्वसनीय अनुभव था।

अभय महाजन ने कहा, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी कहानी में पागलों की तरह प्यार में हैं, जिसमें कुछ भी योजना के अनुसार नहीं होता। ऊप्स! अब क्या? में मेरा किरदार यही है, और मुझे इसका हर पल बेहद पसंद आया। मेरा विश्वास करें, पूरा शो आपको हंसाएगा और इन किरदारों के लिए उत्साहित करेगा। सीरीज ऊप्स अब क्या?, 20 फरवरी को डिज्नी+ हॉटस्टार पर रिलीज होगी।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
www.dakshinbharat.com
epaper.dakshinbharat.com

बेंगलूरु | शनिवार | 08-02-2025 /dakshinbharat /dakshinbharat DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT HINDI DAILY

RNI No. 58061/93. Regn No.:
RNP/KA/BGS/2050/2018-2020
Posted at Bengaluru PSO
Mysore Road Bengaluru-560 026.

फेडरेशन ऑफ इंडियन ग्रेनाइट एंड स्टोन इंडस्ट्री (फिग्सी) के तत्वावधान में इस वर्ष 12 से लेकर 15 फरवरी तक चार दिवसीय प्राकृतिक पत्थरों की प्रदर्शनी 'स्टोना 2025' का आयोजन शहर के तुमकूर रोड स्थित बेंगलूरु इन्टरनेशनल एक्जीबिशन सेन्टर में किया जा रहा है।

सेवा, सरलता, सामंजस्य की भावना से धर्म साधक बनना संभव : आचार्यश्री विमलसागरसूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भद्रावती। शुक्रवार को स्थानीय श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक संघ के पार्श्व भवन में धर्मसभा को संबोधित करते हुए जैनाचार्य विमलसागरसूरीश्वजी ने कहा कि आधुनिक समाज को अधर्म और विज्ञान पर बहुत विश्वास है, पर धर्म पर गहरी श्रद्धा नहीं है। धर्म के नाम पर होते विवाद भी अधर्म का ही रूप है। धर्म तो विवाद नहीं संवाद सिखाता है। मारना नहीं बचाना सिखाता है। धर्म द्वेष और वैमनस्य नहीं, प्रेम व सद्भावना की शिक्षा देता है। यह मात्र उपदेश नहीं, आत्म विश्लेषण और संवेदना का विषय है। बुद्धि से धर्म नहीं होता, श्रद्धा-भक्ति से ही धर्म हो सकता है। शक्ति, संपत्ति या सत्ता से हम धार्मिक नहीं हो सकते, बल्कि सेवा, सरलता, सामंजस्य, सहअस्तित्व की भावना से धर्म साधक बन सकते हैं।

आचार्य विमलसागरसूरीश्वरजी ने कहा कि धर्मतत्व पृथ्वी पर मानवजाति को मिला हुआ अमूल्य वरदान है। इसे संप्रदायों की संकीर्ण व्यवस्थाओं से ऊपर उठकर प्राणिमात्र के कल्याण के रूप में देखा जाना चाहिये। संप्रदायों के स्वरूप, उनकी व्यवस्थाएं, मान्यताएं और नीति-रीति भिन्न-भिन्न हो सकती हैं, लेकिन धर्मतत्व का स्वरूप तो सदैव एक जैसा निर्मल सर्वकल्याणकारी ही होता है। एक बार धर्मतत्व की विस्तृत व्याख्या को समझने का प्रयास करना चाहिए। जो पतन के मार्ग से हमें बचाएं और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाएं, उसे शास्त्रों ने धर्म कहा है। जो सदाचार, संयमित जीवन, दया, दान, साधना, मैत्रीभावना, अहिंसा, करुणा, नैतिकता आदि की शिक्षा-दीक्षा दें, उसे धर्म कहा गया है। जो किसी का बुरा न करें और सबकी भलाई की कामना करें, वह धर्म है। मानों कि धर्मतत्व है तो पृथ्वी टिकी है। धर्म के बिना जीवन व्यर्थ है। दुनिया की कोई भी उपलब्धि धर्मतत्व की बराबरी नहीं कर सकती, इसलिए धर्म की रक्षा, वह स्वयं की रक्षा है। जो धर्म की रक्षा करता है, प्रकारांतर वह अपनी ही रक्षा कर रहा है। इससे पूर्व हल्लीकेरे से पदयात्रा करते हुए आचार्य विमलसागरसूरीश्वरजी, गणि पद्मविमलसागरजी आदि सात श्रमणजन गांधी सर्कल पहुंचे, जहां कलश, श्रीफल और स्वस्तिक से समाज के श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। फिर पार्श्वनाथ जिनालय में सामूहिक चैत्यवंदना हुई। संघ के अध्यक्ष रतनचंद जैन और दिनेश जैन ने बताया कि शनिवार को विविध मंत्रों, मुद्राओं और जड़ीबूटियों से एक सौ आठ पार्श्वनाथ का संगीतमय विशिष्ट अनुष्ठान होगा। प्रभु पार्श्वनाथ के एक सौ आठ प्राचीन तीर्थों के इतिहास की रोचक प्रस्तुति होगी। रात्रिकालीन ज्ञानसत्र में गणि पद्मविमलसागरजी तत्वों की विवेचना करेंगे।

सुरेश बिट्टू बने अध्यक्ष, उत्तमचन्द फिर बने सचिव

जैन मिशन ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी गठित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। चिकबलापुर में संचालित जैन मिशन अस्पताल के जैन मिशन ट्रस्ट की साधारण सभा में अध्यक्ष जितेन्द्र मरड़िया ने सभी का स्वागत किया। उन्होंने घेवरचन्द चुन्नीलाल सुराणा परिवार के प्रति कृतज्ञता जताई तथा जैन मिशन हस्पताल के चेयरमैन डॉ नरपत सोलंकी, फण्ड समिति चेयरमैन शांतिलाल गोटावत, डॉ प्रियांक सोलंकी, राकेश कोठारी, प्रकाश चोपड़ा को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया। सचिव उत्तमचंद कोठारी ने ट्रस्ट के कार्यों की जानकारी दी। चुनाव अधिकारी महेंद्र कोठारी, प्रकाश मुथा एवं गौतम मकाना ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की जिसमें सुरेश जैन (बिट्टू भाई) को ट्रस्ट का अध्यक्ष, लक्ष्मीचन्द भंडारी को उपाध्यक्ष, उत्तमचन्द कोठारी को सचिव, गुलाबचन्द पगारिया को कोषाध्यक्ष, मनीषकुमार खाड़ीवाला को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। इसके अलावा अन्य 8 सदस्यों को कार्यकारिणी समिति में शामिल किया है। नए अध्यक्ष सुरेश जैन ने सेवा के संकल्प को दोहराया। डॉ. नरपत सोलंकी ने अस्पताल और नए ब्लॉक सुराणा ब्लॉक, कानूंगा ब्लॉक एवं मल्होत्रा ब्लॉक के अगले वर्ष तक शुरू होने की जानकारी दी।

आऊवा महिला मंडल की मासिक बैठक सम्पन्न

बेंगलूरु। आऊवा जैन महिला मंडल की मासिक संगोष्ठी हिना कोठारी के निवास पर हुई। अध्यक्ष कांता रायसोनी ने सभी का स्वागत किया। बैठक में गत दिनों दिवंगत हुई उमाबाई रायसोनी के गुणों व योगदान को याद किया गया। इस मौके पर मंडल की विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा हुई। लीला कोठारी ने सबका सम्मान किया। कांता रायसोनी ने संचालन एवं आभार व्यक्त किया।

नेत्र जांच शिविर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के जेसीआई बेंगलूरु कॉस्मों द्वारा शांतिनगर स्थित संध्या किरण आश्रम में करीब 60 लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया। 'दिव्य दृष्टि प्रोजेक्ट' के तहत दिव्य दृष्टि आई हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रकाश जैन की टीम द्वारा निशुल्क आई चेक अप करवाया गया। आई चेकअप में निशुल्क दवाई व चश्मे भी वितरित किए गए। शिविर में अध्यक्ष सुनील मेहर, मंत्री दीपिका जैन, समुदायिक विकास उपाध्यक्ष मोनिका कुमट, उपाध्यक्ष गौतम बोथरा, कोषाध्यक्ष दीपक जैन आदि ने व्यवस्थाओं में सहयोग किया।

बेंगलूरु में 12 फरवरी से सजेगा प्राकृतिक पत्थरों का मेला 'स्टोना 2025'

16वें स्टोना प्रदर्शनी में प्रतिभागियों ने दिखाया सकारात्मक रेस्पांस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। फेडरेशन ऑफ इंडियन ग्रेनाइट एंड स्टोन इंडस्ट्री (फिग्सी) के तत्वावधान में इस वर्ष 12 से लेकर 15 फरवरी तक चार दिवसीय प्राकृतिक पत्थरों की प्रदर्शनी 'स्टोना 2025' का आयोजन शहर के तुमकूर रोड स्थित बेंगलूरु इन्टरनेशनल एक्जीबिशन सेन्टर में किया जा रहा है। इस आयोजन के प्रचार प्रसार के लिए फेडरेशन के पदाधिकारियों ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की जिसमें स्टोना 2025 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

सरकार के सकारात्मक रवैया से आएगा पत्थर बाजार में बदलाव : एस. कृष्णप्रसाद

पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हए फेडरेशन ऑफ इंडियन ग्रेनाइट एंड स्टोन इंडस्ट्री (फिग्सी) के अध्यक्ष एस कृष्णाप्रसाद ने बताया कि 41 वर्ष से फेडरेशन उद्योग, उद्योगपतियों व केन्द्र व विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सामंजस्य सेतू का कार्य करता आ रहा है। आज पूरे देश में फेडरेशन के 1490 से अधिक सदस्य है। उन्होंने बताया कि फिग्सी समय-समय पर विभिन्न सरकारों के साथ पत्थर उद्योग के हित में सामंजस्य बनाने के उदेदश्य से आवश्यक बैठकें करती रहती है। भारत सरकार से भी 'फिग्सी' लम्बे समय से ग्रेनाइट विकास कौंसिल में फिग्सी की भागीदारी व प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की मांग कर रहा है। प्रसाद ने बताया कि आज प्राकृतिक पत्थर उद्योग कच्चे माल की कमी, विनियामक बाधाओं और कृत्रिम सामग्रियों से अनुचित प्रतिस्पर्धा से जूझ रहा है। वर्तमान काल में उद्योग के अच्छे प्रदर्शन और वितरण के लिए अनुकूल माहौल की आवश्यकता है। इसके लिए पत्थर उद्योग की ओर सरकार को गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि सामने आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके और साथ ही समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू किया जा सके। कृष्ण प्रसाद ने कहा कि फेडरेशन पत्थर उद्योग में प्रमुख नीतिगत परिवर्तनों की वकालत कर रहा है, जिसमें गारंटीकृत नवीनीकरण के साथ 50 साल के लिए खदान पट्टे देना, रॉयल्टी दरों को तर्कसंगत व समान बनाना और कच्चे ब्लॉक और स्लैब पर जीएसटी कम करना शामिल है। अध्यक्ष ने बताया कि भारत भूगोलिक दृष्टि से बहुत फैला हुआ है और विभिन्न खनिज अलग अलग राज्य में मिलते हैं जिसके चलते कर, रॉयल्टी आदि में विषमता होती है इसलिए फिग्सी का सरकार से निवेदन है कि 'वन नेशन-वन मिनरल-वन पॉलिसी' का सूत्र अपना चाहिए ताकि पत्थर उद्योग को बढ़ावा मिले तथा भारतीय व्यापारियों, खदानमालिकों व उद्योगपतियों को व्यापार में सहूलियत व कार्य समानता हो। फिग्सी संघ उद्योग को उत्खनन और प्रसंस्करण इकाइयों दोनों में कुशल कार्यबल के लिए सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए होसूर और जयपुर दोनों में प्राकृतिक पत्थर उद्योग के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण केंद्र शुरू कर दिया है और कर्नाटक सरकार से चामराजनगर में शोध केन्द्र स्थापित करने के लिए सहयोग का निवेदन किया है।

स्टोना प्रदर्शनी में विश्व के 18 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल : मनोजकुमार सिंह

फिग्सी के महामंत्री मनोजकुमार सिंह ने बताया कि द्वि-वार्षिक पत्थर मेला स्टोना 2025 दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पत्थर मेला है, जो 46,000 वर्गमीटर से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें इस वर्ष 324 भारतीय स्टॉल व 64 ओवरसीज स्टॉल लगाए जा रहे हैं। कर्नाटक से करीब 60 व राजस्थान से लगभग 200 स्टॉल लगाए जा रहे है। इस वर्ष स्टोना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टर्की, चीन, इटली व इरान के 4 पैवेलियन बनाए गए है। इस पत्थर प्रदर्शनी में भारत के अलावा विश्व के अन्य 18 देश भाग ले रहे है। इस स्टोना प्रदर्शनी में 453 छोटे बड़े स्टॉल लगाए जा रहे हैं। फिग्सी का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक पत्थर उद्योग को बढ़ावा व सशक्तिकरण करना है। प्राकृतिक पत्थर में ग्रेनाइट, मार्बल, सेंड स्टोन, स्लेट, क्वार्टजाइट आदि शामिल है। इस प्रदर्शनी में उपभोक्ता और सभी हितधारकों को एक साथ जुड़ने, सहयोग करने और बढ़ने के लिए एक सक्रिय मंच मिलता है। सिंह ने बताया कि इस वर्ष स्टोना प्रदर्शनी में इस बार 1000 करोड़ के व्यापार का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रदर्शनी में जियोलॉजी सेमिनार सहित अनेक बिजनेस टॉक व उद्योग संबंधित अनेक ज्ञानवर्धक सेमिनारों का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार विश्व प्रसिद्ध अयोध्या मंदिर में विराजित रामलला की पाषाण प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज को प्रदर्शनी में विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। आगे बताते हुए कहा कि इस प्रदर्शनी में स्टोन उद्योग के लिए लाइफ टाइम अवार्ड, ग्रेनाइट व मार्बल खदान, एक्पोर्ट, मशीनरी व टूल सहित जियोलॉजी विद्यार्थी श्रेणी में चयनीत 9 विद्यार्थियों को अवार्ड व नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मान किया जाएगा।

स्टोना 2025 के अधिकतर स्टॉल बुक, बढ़ाया गया प्रदर्शन क्षेत्र : मदनलाल जांगिड़

स्टोना 2025 के चेयरमैन मदनलाल जांगिड ने स्टोना प्रदर्शनी के बारे में बताते हुए कहा कि वर्ष 1987 में स्टोना प्रदर्शनी का पहला आयोजन हुआ था। इस वर्ष इस 16वें स्टोना आयोजन में गत आयोजन से भी ज्यादा जगह यानी एक्जिबिशन सेन्टर के 5 हाल सहित आउटडोर में भी स्टोना प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। एक, दो व तीन हॉल में प्राकृतिक पत्थरों का प्रदर्शन, चौथे व पांचवें हॉल में पत्थर उद्योग संबंधित केमिकल्स, टूल्स, मशीनों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में ज्यादातर प्रतिभागी पूरे भारत वर्ष से होते है, उनके अलावा विभिन्न सरकारी व राज्य सरकारें भी प्रदर्शनी में अपने अपने स्टॉल लगा रही है। स्टोना व्यावसायिक घरानों, कारीगरों, डिजाइनरों के लिए नए अवसर प्रदान करने के लिए एक प्रभावी प्लेटफार्म का कार्य करता है। जांगिड़ ने बताया कि इस बार स्टोना 2025 की बुकिंग के लिए बहुत ही सकारात्मक रेस्पांस मिला है। उन्होंने बताया कि स्टोना के उदघाटन के अवसर पर 12 फरवरी को कर्नाटक के खदान मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन, राज्य परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी व राजस्थान के कामर्स व उद्योग राज्य मंत्री कृष्णकुमार विश्नोई आदि उपस्थित होंगे जबकि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार 15 फरवरी को आयोजित समापन समारोह में शामिल होंगे। शिल्पग्राम के बारे में बताते हुए कहा कि पत्थर की शिल्पकला व मूर्तिकला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिल्पग्राम का आयोजन अलग से किया जा रहा है जिसमें कर्नाटक से 3, राजस्थान से 14, मध्यप्रदेश से 1, ओडिसा से 2, उत्तराखंड से 1 व अन्य 4 शिल्पी अपनी कला की नुमाइश करेंगे। प्रदर्शनी के अलावा इस आयोजन में उद्योग संबंधित अनेक ज्ञानवर्धक सेमिनारों का भी आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में एक्जिबिटर डायरेक्टरी का भी निर्माण किया गया है जिसका विमोचन भी स्टोना प्रदर्शनी में होगा। इस मौके पर पत्रकार वार्ता का संचालन करते हुए पीआर, इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया सबकमेटी के चेयरमैन के. केशवमूर्ति ने बताया कि इस बार स्टोना प्रदर्शनी का सोशल मीडिया पर भी प्रचार किया जा रहा है, उन्होंने उपस्थित सभी पत्रकारों को स्टोना प्रदर्शनी के लिए आमंत्रित किया। स्टोना को चेयरमैन हिमांशु सहगल ने धन्यवाद दिया।

'अनंत सुख पाने के लिए भाव शुद्धि आवश्यक है'

मुमुक्षु संतोषकुमारी कर्नावट की दीक्षा निमित्ते मेहंदी रस्म सम्पन्न

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। स्थानीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ विल्सनगार्डन के तत्वावधान में मुमुक्षु संतोषकुमारी कर्नावट के जैन भागवती दीक्षा महोत्सव में द्वितीय दिवस उपप्रवर्तक नरेशमुनिजी, शालिभद्रमुनिजी, साध्वीश्री सुधाकंवरश्रीजी, दर्शनप्रभाश्रीजी, सुप्रभाश्री एवं डॉ. प्रतिभाश्री आदि साधु साध्वियों के सान्निध्य में मेहंदी रस्म का आयोजन किया गया। इस मौके पर संतश्री नरेशमुनिजी ने प्रेरक प्रवचन में कहा कि हमें अपनी मुक्ति, भवभ्रमण, जीवन में सुख-दुख पर चिंतन करना चाहिए।

संतश्री ने कहा कि पहले मांग कम और आपूर्ति ज्यादा थी पर आज हमारी मांग बढ़ गई है और साधनों की आपूर्ति कम हो गई है जिसके परिणामस्वरुप हमारे जीवन में सुख नहीं है। यदि हमारे भाव शुद्ध नहीं हैं, तो कितना भी कर लो हम सिर्फ और सिर्फ कार्य करने में ही रह जाएंगे। जैसे अशुभ भावों के कारण नरक आयुष्य का बंधन होता है, वैसे ही चक्रवर्ती के पास धन-पशु-प्राणी-सोना- चांदी- रत्न सब पुण्य से मिलता है, इन सब का उपभोग करने और धर्म आराधना नहीं करने पर सारा पुण्य समाप्त हो जाता है और अंत में नरक में जाते हैं। दीक्षा के अनुमोदनार्थ यहां आए हुए श्रीसंघ के एवं सभी श्रद्धालुओं ने पुण्य का उपार्जन किया है।

शालिभद्रमुनिजी ने कहा कि हमें अगर इस संसार से मुक्त होना है तो जीवन में संयम आवश्यक है। जैसे मेहन्दी का रंग हरा होता है, ये उपाध्याय का रंग है और जैसे मेहन्दी सूखने के बाद लाल कलर आता है वैसे ही सिद्ध का कलर भी लाल होता है तो आप पंचम पद में आ रहे हो और आगे आप जल्दी से जल्दी सिद्ध बनो, यही शुभकामनाएं।

साध्वी समृद्धिश्रीजी ने कहा कि ऐसे तो मनुष्य के 303 भेद है लेकिन उसमें से 15 कर्मभूमि में जन्म लेने वाले ही संयम ले सकते हैं। साध्वी परिज्ञाश्री ने कहा कि संयम ही हमारे जीवन का श्रृंगार है। मुमुक्षु संतोषकुमारी मेकअप करते करते अपनी आत्मा का चेकअप करने लगी और वेकअप अर्थात जागृत हो गई। सभा का संचालन संघ के चेयरमैन मीठालाल मकाणा ने किया।

इस अवसर पर अध्यक्ष नेमीचंद भंसाली, मंत्री सज्जन बोहरा, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद पिछोलिया आदि उपस्थित थे। प्रचार प्रसार संयोजक प्रकाशचंद बाफना ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को गणेश बाग जैन स्थानक के प्रांगण में गुरु भगवंतों के सान्निध्य में दीक्षा महोत्सव के अंतर्गत केसर छंटाई का कार्यक्रम होगा।

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com